page 1 and 8 aug 7_page 1 Mar 25 final ds.qxd 07-08-2025 02:00 Page 1

epaper.dehatsandesh.com

3 नेकां ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग दोहराई

5 चोट के कारण पुमास युनाम के खिलाफइंटर मियामी के मैच से बाहर रहेंगे मेसी

8 'निवेश मित्र 3.0' से और आसान होगी यूपी में निवेश की राह

मौसम जम्मू — न्यूनतम 25, अधिकतम 29

E-mail: dehatsandesh@gmail.com

जम्मू-कश्मीर का एकमात्र ग्रामीण दैनिक

देहात संदेश

वर्ष-22, जम्मू तवी, अंक-194 | जम्मू तवी, वीरवार 07 अगस्त, 2025 | मूल्य-3 रूपये- (लेह)4 रूपये | पृष्ठ -8

कर्तव्य भवन में आत्मनिर्भर भारत की कहानी लिखकर विकसित भारत का सपना करेंगे साकार : मोदी

नयी दिल्ली 06 अगस्त । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नवनिर्मित कर्तव्य भवन को संविधान की मूल भावना का उद्घोष बताते हुए कहा है कि इसमें जो नीतियां और निर्णय लिए जायेंगे उनसे आत्मनिर्भर भारत की कहानी लिखने के साथ साथ विकसित भारत का सपना साकार किया जायेगा।

श्री मोदी ने बुधवार को यहां सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत केन्द्रीय सचिवालय भवनों में से एक कर्तव्य भवन-3 का दिन में उद्घाटन किये जाने के बाद शाम को एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस नये भवन से देश को गरीबी से मुक्त करने के साथ साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है।

प्रधानमंत्री ने कर्तव्य भवन को कर्मचारियों तथा पृथ्वी दोनों के अनुकूल बताते हुए कर्मचारियों से लोगों के कामों को सेवाभाव से पूरा करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को नये भवन में अपने कार्यों को यादगार बनाने तथा फाइलों को लेकर नजरिया बदलना होगा और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना होगा।

श्री मोदी ने कहा कि कर्तव्य पथ, संसद भवन , रक्षा भवन,यशो भूमि, युद्ध स्मारक और कर्तव्य भवन के निर्माण का उल्लेख करते हुए कहा कि ये केवल कुछ नये भवन नहीं हैं , अमृत काल में

इन्हीं भवनों में विकसित भारत की नीतियां और निर्णय लिए जायेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले दशकों में यहीं से राष्ट्र की दशा तय होगी।

कर्तव्य भवन के नाम को लेकर उन्होंने कहा कि इस इमारत को बहुत मंथन के बाद कर्तव्य भवन नाम दिया गया है। उन्होंने कहा , ये हमारे संविधान की मूल भावना का उद्घोष करते हैं। उन्होंने गीता के एक शलोक का हवाला देते हुए कहा , हमें फल की इच्छा के बिना कर्म करना चाहिए। कर्तव्य भारतीय संस्कृति में केवल दायित्व तक सीमित नहीं है। कर्तव्य हमारे देश के कर्म प्रधान दर्शन की मूल भावना है। यह केवल इमारत का नाम भर नहीं है ये करोड़ों देशवासियों के सपनों को साकार करने की कर्मभूमि है।

पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भारत के साथ आजाद हुए कितने ही देश इतनी तेजी से आगे बढ गये लेकिन भारत उनकी गति से आगे नहीं बढ पाया। उन्होंने कहा कि हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम समस्याओं को आने वाली पीढियों के लिए छोडकर नहीं जाये।

श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद दशकों तक देश की प्रशासनिक मशीनरी उन इमारतों से चलायी गयी जो ब्रिटिश काल में बनी थी। इनमें स्थिति कितनी खराब थी यहां कार्य करने वालों के लिए पर्याप्त जगह और रोशनी नहीं थी। गृह मंत्रालय सौ वर्षों से एक ही इमारत में अपर्याप्त संसाधनों से चल रहा था। विभिन्न मंत्रालय दिल्ली के 50 अलग अलग जगहों पर चल रहे थे इनमें से कुछ किराये के भवनों से चल रहे थे। इस पर काफी पैसा खर्च हो रहा था। इनके किराये पर डेढ हजार करोड़ रूपया प्रतिवर्ष जा रहा था। उन्होंने कहा कि हजारों कर्मचारियों को एक मंत्रालय से दूसरे में आना जाना पड़ता है इससे कितना समय खराब होता है और गाडियों के लिए पेट्रोल खर्च होता है। नये भवन की सुविधाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इक्कसवीं सदी के भारत को इक्कसवीं सदी की सुविधाएं भी चाहिए जो बेहतरीन हों।

अमेरिका का भारत पर शुल्क बढ़ाने का निर्णय अनुचित और अविवेकपूर्ण : विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 06 अगस्त। विदेश मंत्रालय ने भारतीय उत्पादों पर आयात शुल्क और बढ़ाने के अमेरिका के निर्णय को एक बार फिर अनुचित तथा अविवेकपूर्ण बताते हुए कहा है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बुधवार को भारत का रुख स्पष्ट किया।

उन्होंने एक बयान में कहा कि अमेरिका ने रूस से तेल आयात को लेकर हाल के दिनों में भारत को निशाना बनाया है। सरकार ने इन मुद्दों पर अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि भारत के आयात का निर्णय बाजार के कारकों पर आधारित है और देश के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के समग्र उद्देश्य से लिया गया है।

प्रवक्ता ने अमेरिका के अतिरिक्त शुल्क लगाने के निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, ''यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत पर उन कार्यों के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाने का विकल्प चुना है जो कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हित में कर रहे हैं।

उन्होंने भारत का रुख स्पष्ट करते हुए कहा, ''हम दोहराते हैं कि ये कार्य अनुचित और अविवेकपूर्ण हैं। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

उल्लेखनीय है कि श्री ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर पहले के 25 प्रतिशत अतिरिक्त आयात शुल्क के अलावा आज 25 प्रतिशत और शुल्क लगाने संबंधी कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किये जो 27 अगस्त से प्रभावी होगा। इससे पहले अमेरिका ने पहली अगस्त से भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त आयात शुल्क लगाया था।

अमेरिका ने भारत पर लगाया और 25 प्रतिशत आयात शुल्क

वाशिंगटन, 06 अगस्त। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल की खरीद जारी रखने के कारण भारत पर 25 प्रतिशत और आयात शुल्क लगा दिया है।

श्री ट्रंप ने आपातकालीन प्रावधानों के तहत बुधवार को इस संबंध में एक कार्यकारी आदेश जारी किया।

व्हाइट हाउस द्वारा इस संबंध में जारी फैक्टशीट में कहा गया है कि यह अतिरिक्त आयात शुल्क 27 अगस्त से प्रभावी होगा। इससे पहले अमेरिका ने 01 अगस्त से भारत से आने वाले सामानों पर 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त शुल्क लगाया था। इस प्रकार 27 अगस्त से भारतीय सामानों पर अमेरिका में आयात शुल्क दोगुना हो जायेगा। व्हाइट हाउस ने कहा है कि यह शुल्क विशेष रूप से रूस से भारत के तेल खरीदने के कारण लगाया गया है और प्रशासन अन्य देशों के खिलाफ भी ऐसे मामलों में अतिरिक्त आयात शुल्क लगा सकता है और इसके लिए एक व्यवस्था बनायी जा रही है। इससे पहले, भारत ने रूस से तेल खरीदने पर दंड लगाने की राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी को दोहरा मानदंड बताते हुये कहा था कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन खुद रूस से व्यापार जारी रखे हुये हैं।

खबर संक्षेप

जम्मू-कश्मीर में 13.12 करोड़ रुपये की मनरेगा मज़दूरी बकाया

श्रीनगर, 06 अगस्त। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लोकसभा को बताया कि 30 जुलाई, 2025 तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत जम्मू-कश्मीर पर 13.12 करोड़ रुपये की मज़दूरी बकाया है।

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने एक लिखित उत्तर में बताया कि यह बकाया राशि चालू वित्त वर्ष से संबंधित है और 2024-25 तक की 100 प्रतिशत मज़दूरी देनदारियों का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। उन्होंने कहा, ''मज़दूरी का भुगतान आधार-आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में जमा किया जाता है।

पासवान ने स्पष्ट किया कि आधार-बैंक खाता लिंक न होने के कारण मनरेगा के तहत जॉब कार्ड हटाए नहीं जाते।

हालांकि, उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जॉब कार्ड हटाने या बहाल करने के संबंध में मार्गदर्शन देने के लिए जनवरी 2025 में एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की थी। एसओपी में ग्राम सभा द्वारा सत्यापन, मसौदा विलोपन सूचियों का सार्वजनिक प्रदर्शन, शिकायत निवारण तंत्र और किसी भी रद्दीकरण से पहले लंबित बकाया राशि का निपटान शामिल है।

मंत्री ने कहा कि पीएमजीएसवाई निधि जारी करना एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें उचित प्रक्रिया के बाद सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से दैनिक मंजूरी जारी की जाती है।

एनआईए ने श्रीनगर में हिरासत में लिए गए ओजीडब्ल्यू के घर की तलाशी ली

श्रीनगर, 06 अगस्त। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक टीम ने बुधवार को श्रीनगर के इखराजपोरा इलाके की रुस्तम कॉलोनी में एक आवासीय घर पर आतंकवाद से जुड़ी एक जांच के सिलसिले में छापेमारी की।

वह जम्मू की कोट भलवाल जेल में जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत बंद

यह छापेमारी हाशिम फारूक मीर, फारूक अहमद मीर के बेटे के घर पर की गई जिसकी पहचान एक ओवर ग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) के रूप में हुई है और वह वर्तमान में हिरासत में है। सूत्रों ने बताया कि यह छापेमारी गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 16, 18, एनआईए जम्मू की भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2) के तहत एफआईआर संख्या आरसी 01/2025 के मामले में चल रही जाँच का हिस्सा थी और शुरुआत में यूएपीए की धारा 13, 18, 39, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम (धारा 3/4) और बीएनएस की धारा 103, 109, 115(2) और 3(5) के तहत एफआईआर संख्या 66/2024 कोठीबाग पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। आगे

उपराज्यपाल ने गुरेज में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किया

आदिवासी समुदाय ने देश की सांस्कृतिक विविधता में अपार योगदान दिया है : एलजी सिन्हा

श्रीनगर, गुरेज़ 06 अगस्त। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरेज में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किया। दो दिवसीय जनजातीय महोत्सव दर्द-शिना जनजातीय समुदाय की संस्कृति और परंपरा का जश्न मनाता है।

वर्चुअल माध्यम से उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए, उपराज्यपाल ने देश की सांस्कृतिक विविधता में जनजातीय समुदाय के अपार योगदान की सराहना की। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराज्यपाल ने कहा मैं दर्द-शिना जनजातीय समुदाय को भारत का सबसे अनमोल खजाना मानता हूँ, जो लोगों को अपनी परंपराओं और रीति-रिवाजों को संरक्षित करने के लिए प्रेरित करता है। इसकी समृद्ध परंपराएँ हमारे लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश हैं। दर्द-शिना समुदाय के प्रकृति से गहरे जुड़ाव ने एक अनूठी

संस्कृति और मूल्यों को आकार दिया है। वे मानवता को प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर एक स्थायी जीवन शैली जीने का एक शक्तिशाली सबक देते हैं। उन्होंने कहा ''माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, अमूल्य जनजातीय संस्कृति को संरक्षित किया जा रहा है और उनके प्राचीन गौरव और गरिमा को पुनर्स्थापित किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने हमेशा आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाने और उनके जीवन में बदलाव लाने पर ध्यान केंद्रित किया है। आदिवासियों के खिलाफदशकों से चला आ रहा अन्याय अगस्त 2019 में समाप्त हो गया। विभिन्न परिवर्तनकारी पहलों ने आदिवासी भाइयों और बहनों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया है

उन्होंने कहा, गुरेज़ 1947 के बाद पहली बार 2023 में ग्रिड पावर से जुड़ा है। यह गुरेज़ और दर्द-शिना समुदाय के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस अवसर पर, उपराज्यपाल ने शिना गिलगित 88.8 एफएम रेडियो स्टेशन को दर्द-शिना आदिवासी समुदाय को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि यह सामुदायिक रेडियो स्टेशन युवा पीढ़ी को समुदाय के मूल्यों, ज्ञान और परंपराओं को संरक्षित और संजोने के लिए प्रेरित करेगा। उपराज्यपाल ने सुझाव दिया कि नए रेडियो स्टेशन को एक समर्पित साप्ताहिक कार्यक्रम के माध्यम से आदिवासी समुदाय के समृद्ध इतिहास का प्रसारण करना चाहिए।

जम्मू-कश्मीर में सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए 43,010 करोड़ रुपये की लागत से तीन राजमार्गों को मंजूरी

नई दिल्ली, 6 अगस्त। जम्मू-कश्मीर के बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देते हुए, केंद्र सरकार ने तीन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनका उद्देश्य क्षेत्र में कनेक्टिविटी में बदलाव लाना और सुरक्षा एवं पर्यटन को बढ़ावा देना है। इनमें से पहली परियोजना सांबा से उधमपुर तक की महत्वाकांक्षी चार-लेन राजमार्ग परियोजना है, जिसकी अनुमानित लागत 7,418 करोड़ रुपये है। इस खंड के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पहले ही तैयार हो चुकी है और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अगले तीन वर्षों के भीतर निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

एक बार चालू हो जाने पर, यह राजमार्ग पठानकोट और उधमपुर के बीच यात्रा के समय को काफी कम कर देगा, जिससे वर्तमान यात्रा, जो दो सैन्य क्षेत्रों से होकर गुजरने वाले मौजूदा मार्गों से चार घंटे से अधिक समय लेती है, घटकर लगभग दो घंटे रह जाएगी।

सांबा से उधमपुर तक 43 किलोमीटर लंबा यह नया मार्ग श्रीनगर जाने वाले पर्यटकों के लिए एक विकल्प भी प्रदान करेगा, जिससे वे जम्मू को पूरी तरह से बायपास कर सकेंगे। इस महत्वपूर्ण गलियारे का चयन भारत माला परियोजना के तहत किया गया है, जो इसके राष्ट्रीय महत्व को रेखांकित करता है। दूसरी प्रमुख परियोजना कठुआ-भद्रवाह-डोडा चार-लेन राजमार्ग है, जिसका बजट आवंटन 28,679 करोड़ रुपये है। यह सड़क जम्मू-कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से शुरू होकर कठुआ, बसोहली, बानी और भद्रवाह होते हुए डोडा पहुँचेगी। डोडा में राजमार्ग-44 से जुड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया यह मार्ग वर्तमान में एक राज्य राजमार्ग है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की योजनाओं के तहत इसका व्यापक उन्नयन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, भद्रवाह को हिमाचल प्रदेश के चंबा से 130 किलोमीटर लंब दो-लेन राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से जोड़ने की योजना है, जिसकी अनुमानित लागत 6,913 करोड़ रुपये है, जिससे अंतर-राज्यीय संपर्क और मजबूत होगा।

सभी बैंक बहनों को लोन का कवरेज बढ़ाएं, दूरदराज व दुर्गम क्षेत्रों पर भी करें फोकस : शिवराज

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत किसानों का खरीफ सीजन में ज्यादा से ज्यादा नामांकन करने और ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में स्वयं सहायता समूहों (स्।ल्) की सदस्य बहनों की तरक्की के लिए उन्हें अधिक लोन देने के संबंध में आज सभी बैंकों व राज्य सरकारों की वर्चुअल बैठक ली। उन्होंने सभी बैंकों को निर्देश दिए कि वे महिलाओं को लोन देने के लिए फोकस कर कवरेज बढ़ाएं, साथ ही दूरदराज व दुर्गम क्षेत्रों पर भी फोकस करके काम करें, ताकि बेहतर नतीजे मिल सकें। शिवराज सिंह ने निर्णय लिया कि वर्तमान खरीफ सीजन के फसल बीमा में ज्यादा से ज्यादा

सार्वजनिक व निजी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शिवराज सिंह ने दिए निर्देश

किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए 16 से 30 अगस्त तक देशभर में अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने इस महत्वपूर्ण बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की विकास की गति और दिशा, दोनों देखकर दुनिया हैरान भी है और कुछ परेशान भी। अनेक लक्ष्यों को हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्राप्त किया है। आज हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और तीसरी बनने के कगार पर खड़े हुए हैं। इन उपलब्धियों के पीछे हमारे दोनों विभागों (कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास) का बहुत अहम रोल है। शिवराज सिंह ने कहा कि जैसे बिना गांवों के भारत नहीं जाना जा सकता, वैसे ही बिना खेती के हमारे देश की पहचान ही नहीं है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा, प्राण है।

संसद के मानसून सत्र में जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए उमर ने कई दलों का मांगा समर्थन

श्रीनगर, 6 अगस्त । मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि उन्होंने संसद में अच्छी-खासी उपस्थिति वाले कई दलों को पत्र लिखकर मौजूदा मानसून सत्र में जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एक विधेयक पेश करने में उनका समर्थन मांगा है।

केंद्र ने 5 अगस्त, 2019 को पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था।अब्दुल्ला ने श्रीनगर में संवाददाताओं से कहा कि मैंने उन

सभी दलों को पत्र लिखा है जिनके संसद में अच्छी संख्या में सांसद हैं और उनसे अनुरोध किया है कि वे जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के वादे पर मदद करें और संसद में इस मुद्दे को उठाएं ताकि इसी सत्र में एक विधेयक लाया जा सके और जम्मू-कश्मीर को उसका राज्य का दर्जा वापस मिल सके। मुख्यमंत्री का यह कदम जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा वापस करने की बढ़ती मांग के बीच आया है। उनका यह प्रयास केंद्र को जम्मू-कश्मीर के लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जवाबदेह ठहराने का एक नया प्रयास है।

29 जुलाई को अब्दुल्ला ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित 42 राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने केंद्र पर जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए मानसून सत्र में एक विधेयक लाने का दबाव बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इसे रियायत के रूप में नहीं बल्कि एक आवश्यक सुधार के रूप में देखा जाना चाहिए।

सामाजिक एकता का प्रतीक बन चुकी है कांवड़ यात्रा - मुख्यमंत्री योगी

बरेली, 6 अगस्त। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को नाथ नगरी बरेली में ₹2264 करोड़ की लागत से जुड़ी 545 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों की तुष्टीकरण की राजनीति पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ असमाजिक तत्व कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश रचते हैं, लेकिन समाज की जागरूकता और प्रशासन की तत्परता से ऐसे तत्व विफल हो जाते हैं। यह यात्रा अब सामाजिक एकता का प्रतीक बन चुकी है। बरेली में लाखों श्रद्धालुओं ने नाथ गलियारे में जलाभिषेक कर अपनी आस्थाप्रकट की, जो शहर की नई पहचान बन रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने रोजगार मेले के

माध्यम से चयनित 6000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र व टैबलेट प्रदान किए।

सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा की सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि लोगों की भावनाओं के वितरीत कांवड़ यात्रा को बदमान करने का कुत्सित प्रयास किया गया, लेकिन आज कांवड़ यात्रा की सफलता जागरुक समाज और बेहतरीन कानून-व्यवस्था से उन लोगों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। डबल इंजन की भाजपा सरकार विरासत को विकास के साथ जोड़ कर काम कर रही है। 2017 से पहले बरेली हर तीसरे महीने दंगों की आग में जलता था, अब वह नाथ कॉरिडोर और आध्यात्मिक पर्यटन के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि अब किसी योजना में जाति, मजहब या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। यह नया भारत है, जो सबका साथ-सबका विकास की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। आज बरेली में तेजी के साथ विकास हो रहा है। डबल इंजन की सरकार लोगों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बरेली को ₹2264 करोड़ की 545 परियोजनाओं का तोहफा मिला है, जिसमें ₹1258 करोड़ की 222 परियोजनाओं का लोकार्पण और ₹1004 करोड़ की 322 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है।

बागवानी व्यापार और बाज़ार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक आयोजित

प्रत्येक ज़िले में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा : जाविद डार

जम्मू, 06 अगस्त। जम्मू-कश्मीर के बागवानी, योजना एवं विपणन विभाग ने आज कनाल रोड स्थित कन्वेंशन सेंटर में किसानों को बाज़ारों से जोड़ना विषय पर एक क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया। इस बैठक का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश के फलते-फूलते बागवानी क्षेत्र में बाज़ार संपर्क को मज़बूत करना और कृषि-व्यवसाय साझेदारी को बढ़ावा देना है।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, सहकारिता एवं चुनाव विभाग मंत्री जाविद अहमद डार ने की।

बैठक में जेकेसीआईपी/एचएडीपी के प्रबंध निदेशक, एपीडी, नाबार्ड के महाप्रबंधक, एपीडी के विशेष सचिव, जेके एग्रो के प्रबंध निदेशक, एचपीएमसी के प्रबंध निदेशक, कमान निदेशक और विभिन्न कृषि एवं संबद्ध विभागों जैसे बागवानी, कृषि, पशु एवं भेड़पालन, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन आदि के प्रमुख उपस्थित थे।

इस सम्मेलन में देश भर के प्रमुख बागवानी उत्पादकों, किसान उत्पादक संगठनों, व्यापारियों, निर्यातकों, कृषि

उद्यमियों और संगठित खुदरा श्रृंखलाओं के प्रतिनिधियों सहित विविध हितधारकों ने भाग लिया। यह खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सीधे जुड़ाव के लिए एक जीवंत मंच के रूप में कार्य किया, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करना और जम्मू-कश्मीर के सेब, अखरोट, बासमती चावल, चेरी, पेकानट, नाशपाती और खुबानी जैसे प्रीमियम बागवानी उत्पादों के लिए नए बाजार के रास्ते खोलना था। इस कार्यक्रम में बागवानी उत्पादों की निर्यात क्षमता, उत्तम कृषि पद्धतियों को अपनाना, ई-नाम जैसे ई-मार्केट प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स में नवाचार जैसे विषयों पर केंद्रित बी2बी संवाद, तकनीकी सत्र और ज्ञान-साझाकरण चर्चाएँ शामिल थीं।

स्वस्थ तन और मन के लिए याद रखें 5 नियम

हमारे शरीर की हर प्रणाली आपस में जुड़ी हुई है। इसलिए, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, और हमारा मानसिक स्वास्थ्य हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। हम इन नियमों को नियमों की तरह नहीं मानते हैं, क्योंकि ये जीवन का एक तरीका हैं।

पूरा पोषण लेना

पोषण लेने का मतलब यह नहीं है कि हम हर समय सलाद खाते रहते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि हम अपने शरीर को प्रोटीन, काबोर्हाइड्रेट, वसा से लेकर सभी विटामिन और खनिजों तक सभी पोषक तत्वों से भर दें। यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा कुल कैलोरी सेवन हमारे शरीर संरचना लक्ष्यों के अनुरूप है। यह भी सुनिश्चित करते हुए कि हमारे आहार में हमारे पसंदीदा और मुख्य खाद्य पदार्थ हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे शरीर का 50-60 प्रतिशत हिस्सा पानी से बना है और हमें इष्टतम स्वास्थ्य, मस्तिष्क के कार्य आदि के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है।

व्यायाम और गतिविधि

सप्ताह में कम से कम 3-5 बार व्यायाम करना हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। व्यायाम का कोई भी रूप जो हमारे लिए सुरक्षित है, और जिसका हम आनंद लेते हैं, हम में से अधिकांश के लिए एक अच्छी शुरूआत है। दैनिक आधार पर सक्रिय रहने और अधिक कदम (8-10' कदम) चलने के साथ इसे जोड़ना एक आदर्श संयोजन बनाता है।

इसके बाद नींद आती है

हर रात 75 घंटे से ज्यादा सोना अच्छा होता है। पर्याप्त नींद भी हमारी उत्पादकता में सुधार करती है और लालसा, भूख को कम करती है, सूजन और भावनात्मक प्रतिक्रिया को कम करती है।

तनाव प्रबंधन और दिमागीपन

दूसरी ओर, तनाव प्रबंधन भी उतना ही महत्वपूर्ण है, अगर तनाव को ठीक से प्रबंधित किया जाए, तो यह वास्तव में हमें बेहतर प्रदर्शन करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। याद रखें, हमारे विचारों की गुणवत्ता हमारे जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। इसलिए, हमें सक्रिय रूप से अपने दिमाग पर काम करना चाहिए, खुद को सुधारना चाहिए और अपने मानसिक दोषों को कम करना चाहिए। नियमित रूप से ध्यान करना और कृतज्ञता जर्नलिंग रूटीन रखना इनके लिए एक गेम चेंजर है।

पर्यावरण और नियमित प्रबंधन

पर्यावरण प्रबंधन में हमारे पर्यावरण में सब कुछ शामिल है। किचन में खाने से लेकर हमारी आदतों और सोशल मीडिया पर हम लोगों को फॉलो करते हैं। क्या हम अपने आत्म-विकास और हमारे लिए महत्वपूर्ण लोगों को पर्याप्त समय दे रहे हैं? यह उस तरह के लोगों तक भी फैलता है जिनसे हम खुद को घेरते हैं। खुद से पूछने के लिए कुछ प्रश्न : क्या वे हमें प्रेरित करते हैं? क्या वे हमें और हमारे लक्ष्यों का समर्थन करते हैं? क्या वे हमें सुधारने में मदद करते हैं? क्या हमारी दिनचर्या हमें स्वस्थ बनाती है, हमें मनुष्य बनाती है या हमें अधिक उत्पादक बनाती है? मैं अत्यधिक सुबह और सोने से पहले की दिनचर्या रखने की सलाह दूंगा।

लहसुन-अदरक के सेवन से रहें सेहतमंद

किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इस बात से हम सभी वाकिफ हैं और इसे मजबूत करने के लिए अपनी डाइट में पौष्टिक आहार व सही दिनचर्या का पालन करना भी जरूरी है। साथ ही ऐसी चीजों को अपनी डाइट में शामिल करने की आवश्यकता है, जो हमें अंदर से मजबूत बनाए। हमारी रसोई में वे सारी औषधियां मौजूद हैं जिनके गुणों से हम अभी भी अनजान हैं।

जी हां, आप अदरक-लहसुन का इस्तेमाल खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए जरूर करते होंगे, लेकिन क्या आप इसके सेहत लाभ के बारे में जानते हैं? लहसुन-अदरक के सेवन से आप निरोगी काया पा सकते हैं। लेकिन इसी के साथ इसका सेवन कैसे करना है, इस बारे में भी हमें पता होना आवश्यक है। अधिकतर लोग यह सोचते हैं कि केवल खाने में ही अदरक-लहसुन का सेवन काफी है लेकिन इसके अलावा भी आपको इनका सेवन करना चाहिए, क्योंकि खाने के पकने के दौरान इनके गुण कम हो जाते हैं। आइए जानते हैं इस लेख में लहसुन-अदरक के फायदों व सेवन करने के सही तरीके के बारे में।

इम्यून सिस्टम को कैसे करें मजबूत?

इम्यून को मजबूत करने के लिए लहसुन का इस्तेमाल करें। इसे खाने में पका के खाने की बजाय इसके छोटे-छोटे टुकड़े कर लें। कुछ देर इन्हें हवा लगने दें। लहसुन में एंटीमाइक्रोबियल तत्व पाया जाता है। ये तत्व वायरस, बैक्टीरिया व फंगस के खिलाफ काम करते हैं। लहसुन खाने से एंटीवायरस प्रोटेक्शन भी मिलता है।

लहसुन कैसे खाएं

इसके छोटे-छोटे टुकड़े कर लें। इसे आप खाना खाने के बाद पानी के साथ ले सकते हैं। लहसुन को चबा-चबाकर खाने की बजाए इसे पानी के साथ सीधा निगल लें। इस तरह से लहसुन का सेवन करने से यह ज्यादा फायदेमंद होता है। लहसुन को 25 से 30 दिन नियमित खाने के बाद आपके अंदर से लहसुन की खूशबू आना शुरू हो जाएगी तब आप समझ जाएं कि इससे अधिक आपको लहसुन का सेवन नहीं करना है। लहसुन कई लोगों को हजम नहीं होता है। इसके लिए आप इसका सेवन एकसाथ न करें व धीरे-धीरे इसकी आदत डालें। शुरुआत के समय आप लहसुन के एकदम छोटे से हिस्सा का सेवन करें, फिर इसी तरह धीरे-धीर इसे बढ़ाएं। जब आप लहसुन ले रहे हैं तो इसके साथ दही का सेवन भी करें।

अदरक

अदरक औषधीय गुणों से भरपूर है। इसके सेवन से आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रख सकते हैं। इसका नियमित सेवन आपको कई स्वास्थ्य लाभ देगा।

अदरक को कैसे खाएं?

अदरक को बिलकुल बारीक पीस लें व कद्दूकस करें। आपको अदरक 1 चम्मच लेना है। इसमें 6 गिलास पानी डालें। अब इसे उबलने दें। जब यह पानी 3 गिलास हो जाए तो इसे 1 कप में निकाल लें। इसे आप गुड़ या शहद के साथ भी ले सकते हैं। दिनभर में एक बार इसका सेवन करें।

जानिए मुलेठी के ये गजब के फायदे

मुलहठी स्वाद में मीठी होने के साथ-साथ कई औषधि गुणों से भरपूर है। इसके सेवन से न सिर्फ खांसी में आराम मिलता है बल्कि इसके कई फायदे भी है। इसका इस्तेमाल आंखों के रोग, मुंह के रोग, गले के रोग, दमा, दिल के रोग, घाव के उपचार के लिए सदियों से किया जा रहा है आइए जानते हैं मुलहठी के गजब के फायदों के बारे में.

- अगर आप सूखी खांसी या गले की समस्याओं से परेशान हैं, तो मुलहठी आपके काम की चीज है। काली मिर्च के साथ पीस कर मुलहठी का सेवन, सूखी खांसी में तो लाभकारी है ही, साथ ही इसे चूसने या उबालकर सेवन करने से गले की खराश, दर्द आदि में भी लाभ होता है।
- मुलहठी चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने का काम करती है। इसे घिसकर लगाने पर चेहरे के दाग और मुंहासे ठीक हो जाते हैं, साथ ही यह आपकी त्वचा को जवा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- मुलहठी रक्त को भी शुद्ध करती है जिससे त्वचा की समस्याएं नहीं होती।
- दूध के साथ मुलहठी का सेवन शरीर की ताकत में वृद्धि करता है। इसके अलावा घी व शहद के साथ मुलहठी का प्रयोग करने से हृदय से संबंधित समस्याएं नहीं होती।
- मुंह में छाले हो जाने की स्थिति में मुलहठी चूसना, इसके पानी से कुल्ला करना और उसे पीना बहुत जल्दी छालों से राहत देता है। साथ ही मुलहठी आवाज को मधुर और सुरीली बनाने के लिए भी उपयोग की जाती है।
- पेट के अल्सर में मुलहठी का सेवन ठंडक देने के साथ ही लाभप्रद होता है। आंत की टीबी होने की स्थिति में भी मुलहठी फायदेमंद उपाय है।
- त्वचा या शरीर में कहीं जल जाने पर भी मुलहठी के चूर्ण और मक्खन का लेप एक कारगर उपाय है, साथ ही यह आंखों की रौशनी में भी वृद्धि करती है।

पेट से जुड़ी समस्याओं से हैं परेशान तो इन आसान उपायों से पाएं छुटकारा

लाइफस्टाइल में बदलाव का सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है। गलत खान-पान आपकी सेहत को प्रभावित करता है, ऐसे में पेट से जुड़ी समस्या का होना आम बात है। जैसे पेट दर्द, गैस, पेट का फुलना आदि। वहीं कुछ लोग पेट अच्छी तरह साफ न होने की शिकायत रहती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप पेट साफ न होने की समस्या से निजात पा सकते हैं।

- बदहजमी से परेशान है, तो आपको पुदीने का सेवन करना चाहिए। पुदीना पेट को साफ करने में मदद करता है। इसका सेवन आप चटनी के रूप में भी कर सकते है।
- सौंफ और सफेद जीरा पाउडर को पहले तवे पर भून लें और फिर उसे मिलाकर पीस लें। अब इस पाउडर का सेवन या तो दिन में एक बार करें या फिर अगर पेट साफ न होने की समस्या से ज्यादा परेशान हैं, तो इसका सेवन दो से तीन बार करें। आपको पेट साफ न होने की समस्या से राहत मिलेगी।
- नियमित रूप से सुबह के समय गुनगुना पानी पीने की आदत बनाएं। इसके कई फायदे हैं। यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और शरीर से सभी विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। साथ ही पेट से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलती है।
- अजवाइन का बीज गैस और बदहजमी की समस्या को दूर करता है और तुरंत पेट को साफ करता है। इसके लिए आप अजवाइन के बीज को भूनकर रख लें और खाना खाने के बाद कुछ बीजों को रोज चबाएं।

आलू का करें छिलके सहित इस्तेमाल जानिए इसके लाभ

सब्जी बनाते समय हम जब आलू का इस्तेमाल करते है, तो आमतौर पर लोग इसके छिलके निकाल कर फेंक देते है, और इसके बाद ही आलू का इस्तेमाल करते है, लेकिन क्या आप जानते हैं आलू को छिलके सहित इस्तेमाल करने के क्या सेहत लाभ मिलते हैं।

ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है

आलू में भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, जो कि ब्लड प्रेशर को रेग्युलेट करने में मदद करता है।

मेटाबॉलिज्म ठीक रखता है

आलू के छिलकेमेटाबॉलिज्म को भी सही रखने में मददगार होते है। इन्हें खाने से नर्व्स को मजबूती मिलती है।

एनीमिया से दूर रखता है

आलू के छिलकेमें आयरन भी भरपूर मात्रा में होता है जिससे एनीमिया होने का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है।

ताकत

आलू के छिलकेमें भरपूर मात्रा में विटामिन बी3 पाया जाता है, जो कि शरीर को ताकत देने का काम करता है।

फाइबर से भरपूर

हमारी डाइट में फाइबर की कुछ मात्रा जरूर शामिल होना चाहिए और आलू के छिलकेमें अच्छी मात्रा में फाइबर्स होते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बूस्ट करने का काम करते है।

क्या खाना खाने के बाद चलना सेहतमंद है?

वॉकिंग करना यानी टहलना कई वजहों से हेल्थ के लिए फायदेमंद ही है। इसस दिल स्वस्थ रहता है, कैलोरी बर्न करने में मदद मिलती है, मूड को बेहतर बनाता है। लेकिन क्या खाना खाने के बाद वॉकिंग करना हेल्दी है? स्टडी से पता चलता है कि यह शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है।

यह ब्लड शुगर को रखता है मैंटेन

डायबिटीज मैनेजमेंट में एक अहम हिस्सा आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती है। टाइप 2 डायबिटीज रोगियों के साथ एक कंट्रोल्ड ट्रायल में पाया गया कि जो लोग अपने मुख्य भोजन के बाद वाकिंग करते थे उनका शुगर लेवल उन रोगियों की तुलना में कम था जो दिन में सिर्फ एक बार चलते थे।

दिल के लिए है अच्छा

एक्सरसाइज आपके दिल को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर दिन चलने से आपको हृदय रोग का खतरा कम हो सकता है। दरअसल करेंट ओपिनियन इन कार्डियोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार वाकिंग करना कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, ब्लड सर्कुलेशन और ब्लडप्रेशर के लिए फायदेमंद होता है। इस तरह खाना खाने के बाद चलना आपके दिल की देखभाल करने का एक अच्छा तरीका है।

पाचन को रखता है दुरुस्त

रिसर्च कहती है कि फिजिकल एक्टिविटी के एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी के कारण खाना खाने के बाद चलना पाचन में सुधार कर सकता है। एक्सरसाइज से अपनी आंतों में फैट, लिपिड और ग्लूकोज मेटाबोलिज्म के परिवर्तनों को कम करने में मदद करते हैं जो इन्फ्लेमेटरी स्थितियों को कम कर सकते हैं।

लेकिन दुष्प्रभाव भी हैं

खाने के बाद वॉकिंग करना पेट में तकलीफ की वजह भी बन सकता है। इनमें अपच, मतली, उल्टी, पेट फूलना, गैस, दस्त, और दर्द शामिल हैं। यह एक हाई कार्बोहाइड्रेट सेवन या हाल ही में खाए गए खाद्य पदार्थों के पाचन में समस्याओं के कारण होता है। इससे बचने के लिए आपको चलने से 30 मिनट पहले इंतजार करना चाहिए।

चलना या वॉकिंग करना ऐसी एक्टिविटी है जिसे आप आसानी से अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं। लेकिन क्या खाना खाने के बाद चलना सेहतमंद है?

स्वामी, प्रकाशक एवं मुंद्रक – नीलम सिंह गिल द्वारा देहात संदेश, गुरूद्वारा सुंदर सिंह रोड़, जम्मू से प्रकाशित एवं नार्थलाईनस पबलिशर्स, 18-बी, फेस- 2, इंडस्ट्रियल इस्टेट, गंग्याल जम्मू से मुद्रित। संपादक– नीलम सिंह गिल। फोन नंबर : (95) 191-2574109, 2548103 RNI Regd. No: JKBIL/2004/13144 Email: dehatsandesh@gmail.com, dehatsandesh@yahoo.com, dehatsandesh@rediffmail.com

स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतर्गत 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान का आयोजन किया

कद्दुआ 06 अगस्त (हि.स.)। राजकीय जीएलडीएम डिग्री कॉलेज हीरानगर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतर्गत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में बुधवार को कॉलेज के ईको क्लब और एनएसएस इकाई द्वारा संयुक्त रूप से एक विशाल वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम में 50 से अधिक छात्रों ने उत्साहपूर्वक और सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसमें विभिन्न फलदार और औषधीय पौधों जैसे अर्जुन, भेलपत्र, अमरूद, हरड़, आंवला और नीम आदि के पौधे रोपे गए। छात्रों को एक सत्यनिष्ठा शपथ भी दिलाई गई, जिसमें उन्हें पेड़ लगाकर, उनकी देखभाल करके और उनका पोषण करके पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया गया। यह कार्यक्रम कॉलेज की प्राचार्या डॉ. प्रज्ञा खन्ना के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन प्रो. नीरू शर्मा (संयोजक इको क्लब) और प्रो. शापिया शमीम (एनएसएस पीओ) के प्रयासों से हुआ।

संकाय सदस्यों डॉ. राजेश शर्मा, प्रो. राकेश शर्मा, बलबीर सिंह, डॉ. विजय कुमार, प्रो. सुरिंदर कुमार, प्रो. नम्रता, प्रो. गंगा शर्मा, डॉ. रजनी बाला, प्रो. बलविंदर कौर, डॉ. रिधम बख्शी, सुरेश शर्मा, राज कुमार, कुलदीप कुमार और विजय कुमार ने भी पूरे जोश और उत्साह के साथ भाग लिया।

जीसीओई जम्मू में प्रेरणादायक गेस्ट लेक्चर का आयोजन

जम्मू, 6 अगस्त (हि.स.)। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन (जीसीओई), जम्मू में भारत की 79वीं स्वतंत्रता दिवस और विकसित भारत 2047 की संकल्पना के उपलक्ष्य में एक प्रेरणादायक अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त मेजर जनरल एस.के. शर्मा ने शिरकत की, जो एक वीर सैनिक होने के साथ-साथ प्रतिष्ठित शिक्षाविद् भी हैं।

उन्होंने आईटीईपी के दूसरे बैच के छात्रों को संबोधित किया। कार्यक्रम की शुरुआत देशभक्ति से ओत-प्रोत प्रार्थना और मुख्य अतिथि को पुष्पांजलि अर्पण के साथ हुई। प्राचार्या डॉ. ज्योति परिहार ने अपने स्वागत भाषण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की महत्ता और आईटीईपी के माध्यम से भावी शिक्षकों को भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य पर प्रकाश डाला।

अपने मुख्य व्याख्यान में मेजर जनरल (से.नि.) एस.के. शर्मा ने एम्पॉवरिंग टीचर्स एन्ड डेवलपिंग लीडरशिप स्किल्स फॉर ए बेटर फ्यूचर विषय पर अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि युवा शिक्षक प्रशिक्षुओं को ईमानदारी, नवाचार और राष्ट्र निर्माण के पथ-प्रदर्शक बनना चाहिए। जम्मू के इस गौरवशाली सपूत ने अनुशासन, चरित्र निर्माण, तकनीकी जागरूकता और सेवा भावना को शिक्षक बनने की मूलभूत शर्तें बताया।

नेकां ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग दोहराई

जम्मू, 6 अगस्त (हि.स.)। जम्मू एवं कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष एडवोकेट रतन लाल गुप्ता ने एक बार फिर केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल करने की पुरजोर मांग की है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बार-बार उपयुक्त समय की बात करते हैं, लेकिन अब यही सबसे उपयुक्त समय है कि जम्मू-कश्मीर की राज्यता को बहाल कर जनता के भारी जनादेश का सम्मान किया जाए। उन्होंने मांग की कि वर्तमान संसद सत्र में इस विषय पर विधेयक लाया जाए।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार ने केवल 9 महीनों में कई चुनावी वादों को पूरा कर शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और स्पष्ट दिशा सुनिश्चित की है।

इस अवसर पर इकबाल खुराना के नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का स्वागत करते हुए रतन लाल गुप्ता ने पार्टी को जन आंदोलन बताते हुए कहा कि यह सदैव जम्मू-कश्मीर की जनता के न्यायसंगत अधिकारों के लिए संघर्ष करती रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इकबाल खुराना की पार्टी में सक्रियता से संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूती मिलेगी। पार्टी के प्रांतीय सचिव शेख बशीर अहमद और विजय लोचन (एनसी एससी सेल चेयरमैन) ने भी इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा वंचित वर्गों के हितों की रक्षा की है, जबकि पूर्ववर्ती सरकारों ने दलित समुदाय की उपेक्षा की। उन्होंने दोहराया कि पार्टी दलितों के उत्थान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। वहीं इकबाल खुराना ने पार्टी की विचारधारा और मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और कहा कि वे जम्मू-कश्मीर को शांति और विकास की ओर ले जाने में पूरी निष्ठा से योगदान देंगे।

बागवानी व्यापार और बाज़ार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक आयोजित

जम्मू 06 अगस्त (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर के बागवानी, योजना एवं विपणन विभाग ने आज कनाल रोड स्थित कन्वेंशन सेंटर में किसानों को बाज़ारों से जोड़ना विषय पर एक क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया। इस बैठक का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश के फलते-फूलते बागवानी क्षेत्र में बाज़ार संपर्क को मज़बूत करना और कृषि-व्यवसाय साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, सहकारिता एवं चुनाव विभाग मंत्री जाविद अहमद डार ने की। इस सम्मेलन में देश भर के प्रमुख बागवानी उत्पादकों, किसान उत्पादक संगठनों, व्यापारियों, निर्यातकों, कृषि उद्यमियों और संगठित खुदरा श्रृंखलाओं के प्रतिनिधियों सहित विविध हितधारकों ने भाग लिया। यह खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सीधे जुड़ाव के लिए एक जीवंत मंच के रूप में कार्य किया, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करना और जम्मू-कश्मीर के सेब, अखरोट, बासमती चावल, चेरी, पेकानट, नाशपाती और खुबानी जैसे प्रीमियम बागवानी उत्पादों के लिए नए बाजार के रास्ते खोलना था।

जम्मू ईस्ट में फ्लाईओवर पर ब्लैकटॉपिंग कार्य शुरू

जम्मू, 6 अगस्त (हि.स.)। जम्मू शहर के नागरिकों को बेहतर शहरी ढांचा उपलब्ध कराने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए जम्मू ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता युधवीर सेठी ने ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह चौक से शुरू होने वाले फ्लाईओवर पर ब्लैकटॉपिंग कार्य का उद्घाटन किया। लगभग 2 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा यह प्रोजेक्ट लोक निर्माण विभाग की देखरेख में पूरा किया जा रहा है। इस अवसर पर भाजपा जिला प्रवक्ता रमन शर्मा, एईई नीरज चोपड़ा, पीडब्ल्यूडी अधिकारी और भाजपा कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युधवीर सेठी ने कहा, यह परियोजना हमारे क्षेत्र की सड़कों और फ्लाईओवर के सौंदर्य और उपयोगिता को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का सहयोग के लिए आभार जताया और कहा कि इस फ्लाईओवर के सुंदरीकरण और मजबूती से हजारों दैनिक यात्रियों को लाभ मिलेगा। विधायक सेठी ने कहा कि जम्मू ईस्ट एक व्यावसायिक और प्रवेश द्वार क्षेत्र होने के नाते यहां की आधारभूत संरचना का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत केवल ब्लैकटॉपिंग ही नहीं बल्कि साइन बोर्ड और फ्लाईओवर की खूबसूरती को बढ़ाने का भी कार्य शामिल है।

साइबर अपराध पर छात्रों को किया जागरूक

जम्मू, 6 अगस्त (हि.स.)। अपने सतत आउटरीच और जन-जागरूकता प्रयासों के तहत भारतीय सेना ने हरनी हायर सेकेंडरी स्कूल में साइबर अपराध पर एक महत्वपूर्ण व्याख्यान आयोजित किया। इस सत्र में 144 छात्रों और 7 शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। व्याख्यान का उद्देश्य छात्रों को इंटरनेट और सोशल मीडिया के सुरक्षित व जिम्मेदार

उपयोग के प्रति जागरूक करना था। डिजिटल दुनिया में बढ़ते खतरों और ऑनलाइन सतर्कता की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया

ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए नुक्कड़ नाटक 'नशे की अदालत' का मंचन

जम्मू, 6 अगस्त (हि.स.)। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत और 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की पूर्व गतिविधियों के रूप में, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कैनाल रोड, जम्मू की एनसीओआरडी कमेटी ने एक प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक नशे की अदालत का आयोजन किया। कार्यक्रम का आयोजन प्राचार्या डॉ. ज्योति परिहार के कुशल मार्गदर्शन में किया गया।

इस नुक्कड़ नाटक का उद्देश्य छात्रों और आम जनता को नशे की लत के गंभीर दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना और स्वस्थ, नशा-मुक्त जीवन के महत्व को रेखांकित करना था।

छात्रों ने अपनी दमदार प्रस्तुति और कहानी के माध्यम से नशे के सामाजिक और कानूनी परिणामों को प्रभावी ढंग से दर्शाया, साथ ही पुनर्वास, सामुदायिक सहयोग और सामूहिक जिम्मेदारी की अहम भूमिका पर भी प्रकाश डाला।

डॉ. ज्योति परिहार ने एनसीओआरडी कमेटी और छात्रों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सामाजिक चेतना फैलाना

और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभाना शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रति कॉलेज की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस आयोजन को सफल बनाने में प्रो. रमज़ान अली (एनसीओआरडी कमेटी संयोजक), प्रो. रूपा कुमारी, डॉ. शालिनी शर्मा और डॉ. अम्बिका कुमारी की सक्रिय भूमिका रही। कार्यक्रम में वरिष्ठ संकाय सदस्य प्रो. सुनंदा रानी, प्रो. अनुराधा चौधरी, डॉ. सुषमा बाला और डॉ. शालू जसरोतिया की उपस्थिति ने छात्रों का उत्साह और भी बढ़ाया

हमारी रियासत, हमारा हक के तहत कांग्रेस ने फिर उठाई राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग

जम्मू, 6 अगस्त (हि.स.)। जम्मू के कुंजवानी चौक पर कांग्रेस पार्टी ने अपने चौराहे पे चर्चा अभियान के तहत एक जनसभा आयोजित कर जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर आवाज बुलंद की। यह कार्यक्रम पंच गोविंद राम सालगोतरा, किसान नेता मनीदीप चौधरी, मोहिंदर और जीत चौधरी के सहयोग से आयोजित किया गया, जिन्होंने स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं को संवाद कार्यक्रम में सक्रिय रूप से जोड़ा। सभा की प्रमुख विशेषता रही वरिष्ठ कांग्रेस नेता और डीडीसी सदस्य सुचेतगढ़ तरणजीत सिंह टोनी का तीखा संबोधन। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सत्ता का अधिकार जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के पास होना चाहिए, न कि मोदी सरकार द्वारा नियुक्त किए गए लोगों के पास। यह लोकतंत्र की हत्या के समान है। टोनी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की जनता को मौन बना दिया गया है और निर्वाचित सरकार की अनुपस्थिति में आम जनता की समस्याएं अनसुनी रह गई हैं। उन्होंने कहा कि दैनिक वेतनभोगियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की वर्षों पुरानी मांगें अभी भी लंबित हैं, बेरोजगारी चरम पर है और युवाओं को रोजगार व समर्थन नहीं मिल रहा, ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में विकास ठप पड़ा है, किसानों को फसल का उचित मूल्य, मुआवजा व कृषि सुधार नहीं मिल पा रहे, परिवहन क्षेत्र अब भी महामारी के बाद के आर्थिक झटकों से जूझ रहा है, और सरकार की कोई ठोस नीति नहीं है। उन्होंने कहा, ये सिर्फ मांगे नहीं, इंसाफ की पुकार हैं और इन्हें सिर्फ जनता द्वारा चुनी गई, जवाबदेह सरकार ही पूरा कर सकती है। इस अवसर पर राकेश कुंडल, पवन कुमार और कैप्टन चौधरी जैसे कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने भी विचार रखे और जनभागीदारी वाली शासन प्रणाली को बहाल करने पर बल दिया।

छतरल हायर सेकेंडरी स्कूल में योग पर व्याख्यान आयोजित किया, छात्रों में दिखा उत्साह

जम्मू, 6 अगस्त (हि.स.)। स्वास्थ्य, कल्याण और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयासों के तहत भारतीय सेना ने मेंढर के छतरल हायर सेकेंडरी स्कूल में योग के लाभों पर एक जागरूकता व्याख्यान आयोजित किया। इस कार्यक्रम में 240 से अधिक छात्रों, शिक्षकों और स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। व्याख्यान का उद्देश्य युवाओं के बीच योग के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक लाभों को उजागर करना था। वक्ताओं ने बताया कि योग को रोज़मर्रा की दिनचर्या में शामिल करने से एकाग्रता में वृद्धि, तनाव में कमी और शारीरिक फिटनेस में सुधार होता है जो छात्रों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। सेना के अधिकारियों ने बताया कि योग केवल शरीर को मजबूत नहीं करता, बल्कि अनुशासन, आंतरिक शांति और मानसिक दृढ़ता भी विकसित करता है जो व्यक्तिगत विकास और राष्ट्र निर्माण दोनों के लिए आवश्यक गुण हैं। सत्र के दौरान छात्रों को प्राणायाम, सरल योग आसन और माइंडफुलनेस अभ्यासों से परिचित कराया गया। छात्रों ने पूरे उत्साह से भाग लिया और योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने में रुचि दिखाई।

यह पहल भारतीय सेना के व्यापक आउटरीच कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य युवाओं से जुड़ाव बढ़ाना, स्वस्थ आदतें अपनाना और राष्ट्र निर्माण के मूल्यों को प्रोत्साहित करना है। सेना ने भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों को जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई, जिससे क्षेत्र के युवाओं के समग्र विकास में सहायता मिले।

डॉ. सुधा शर्मा को एनआईजीएफ की महासचिव नियुक्ति पर उन्हें किया सम्मानित

जम्मू, 6 अगस्त (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जम्मू-कश्मीर की उपाध्यक्ष रेखा महाजन ने बुधवार को मदान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की वरिष्ठ गायनोकोलॉजिस्ट डॉ. सुधा शर्मा को नॉर्थ इंडिया गायनोकोलॉजिस्ट फोरम (एनआईजीएफ) की महासचिव नियुक्त होने पर सम्मानित किया। यह सम्मान हाल ही में झांसी में आयोजित एनआईजीएफ की राष्ट्रीय कांफ्रेंस के दौरान उन्हें प्रदान किया गया। डॉ. सुधा शर्मा को महिलाओं के स्वास्थ्य क्षेत्र में तीन दशकों से अधिक समय तक समर्पित सेवा के लिए जाना जाता है। उन्हें इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी की प्रेसिडेंट इलेक्ट भी चुना गया है। वे राष्ट्रीय स्तर पर भी सक्रिय रही हैं और एफओजीएसआई के जर्नल (जेओजीआई) की एडवाइजरी और जर्नल कमेटी में पाँच वर्षों तक सदस्य रही हैं। उन्होंने 90 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए हैं, 11 मेडिकल पुस्तकों में अध्याय लिखे हैं और रजोनिवृत्ति एवं महिला स्वास्थ्य से

संबंधित 10 महत्वपूर्ण पुस्तकों का संपादन किया है। रेखा महाजन ने इस अवसर पर डॉ. सुधा शर्मा की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा, डॉ. सुधा महिलाओं के सशक्तिकरण और व्यावसायिक उत्कृष्टता की प्रतीक हैं। उनका समर्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें वे महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को सशक्त भारत की नींव मानते हैं। रेखा ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहन और पहचान मिल रही है और डॉ. शर्मा की यह उपलब्धि इसी प्रगति का एक उज्ज्वल उदाहरण है।

भाजपा ने राजौरी में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया

राजौरी , 6 अगस्त (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर ने राजौरी में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया जिसका उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देकर तिरंगा यात्रा को और अधिक प्रभावशाली बनाना था। यह कार्यक्रम भाजपा जिला राजौरी के अध्यक्ष देव राज शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था और इसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्यों सहित प्रमुख उपस्थित थे।

भाजपा जम्मू कश्मीर के महासचिव बलदेव सिंह बिलावरिया ने सभा को संबोधित किया और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में तिरंगा यात्रा के महत्व पर बल दिया। उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान के तहत घर-घर जाकर राष्ट्रीय ध्वज वितरित करने की पार्टी की पहल के बारे में विस्तार से बताया। बिलावरिया ने नागरिकों से राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने और इसे अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर गर्व से फहराने का आग्रह किया। बिलावरिया ने कहा तिरंगा यात्रा न केवल हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करती है बल्कि एकता, अखंडता और देशभक्ति की भावना को भी मजबूत करती है।

हमारा लक्ष्य प्रत्येक नागरिक में अपने देश के प्रति गर्व जगाना और सामूहिक रूप से जम्मू कश्मीर को विकास और समृद्धि की ओर ले जाना है। युवाओं में देशभक्ति के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बिलावरिया ने कहा कि युवा पीढ़ी को एक सशक्त भारत के निर्माण में योगदान के लिए प्रेरित करना भाजपा की प्राथमिकता है। उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से देशभक्ति और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की।

इसके अतिरिक्त, बिलावरिया ने भारत के विभाजन के दर्दनाक परिणामों को प्रतिबिंबित करने के लिए 14 अगस्त को 卐विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस卐 के रूप में मनाने के पार्टी के निर्णय की घोषणा की। उन्होंने इस दिन मंडल स्तर पर मौन जुलूस और संगोष्ठियों का आयोजन करने का आह्वान किया ताकि उन पूर्वजों के बलिदानों का सम्मान किया जा सके जिन्होंने बड़ी चुनौतियों के बावजूद एकता और भाईचारे को कायम रखा।

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, MECHANICAL & HOSPITAL DIVISION JAMMU

NOTICE INVITING TENDER

(SHORT TERM)

MHDJ/e-NIT 156 of 2025-26

Dated: 05.08.2025
Due : 18.08.2025

On behalf of the President of India, e-tenders in two cover system on turnkey basis are invited from registered/reputed firms having sufficient relevant experience for the work mentioned below

S No	Description of work	Project Authority	Estt	Earnest Money Deposit	Cost of tender document	Time of completion	Eligibility Criterion of Bidder
1	Complete Servicing of DG Set-Unit No.4 of Capacity 750 KVA of Sudhir Make installed at Govt. Super Specaility Hospital , Jammu.	Principal GMCH Jammu	1.36 LACS	Rs 3000.00 in the Shape of CDR/FDR/TDR valid for 12 months pledged to the Executive Engineer MH Division Jammu	Rs 200.00 in the shape of Challan through J&K Govt. Treasury indicating Treasury Voucher No. & date and also indicating the name of work duly credited to 0059-PWD (Revenue) and uploading a copy of treasury challan / receipt on e-tendering portal. OR The bidder may deposit tender fee in the shape of e-Challan through Account no. 0097010100002163 in the name of Executive Engineer Mechanical & Hospital Division Jammu Name of Bank: J&K Bank Town Hall Jammu Branch Code:0097 IFSC code: JAKA0TNHALL MICR CODE: 180051025	10 days	Registered & Reputed firms having sufficient experience as per Annexure "C" similar nature of work

THE NIT CONSISTING OF Qualifying INFORMATION, ELGIBILITY CRITERIA, BILL OF QUANTITIES (BOQ) SETS OF TERMS & CONDITIONS OF CONTRACT & OTHER DETAILS CAN BE VIEWED / DOWNLOADED FROM THE WEBSITE www.jktenders.gov.in

DIP/J-4362/25
Dtd: 6-8-2025

Sd/-
(Er. Vishal Mahajan)
Executive Engineer
Mechanical & Hospital Division
Jammu

संपादकीय

इस बार क्या अलग है?

विद्युत विकास विभाग द्वारा अपनी एमनेस्टी योजना को कई दिनों तक जारी रखना लगभग आम बात हो गई है, इस उम्मीद में कि जल्द ही वह दिन आएगा जब सभी संस्थाएँ जिनके बिजली बिल बकाया हैं, उन्हें चुका देंगी और बिना किसी अनिर्धारित कटौती और लोड शेडिंग के बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करके उक्त विभाग को सुचारू रूप से कार्य करने की अनुमति देंगी। इसी संदर्भ में, विद्युत विभाग ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एमनेस्टी योजना को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया है, जिससे लंबित बिजली बकाया वाले परिवारों को काफी राहत मिली है। विद्युत विकास विभाग द्वारा जारी सरकारी आदेश संख्या 114-जेकेपीडीडी 2025 के अनुसार, विस्तार उन्हीं नियमों और शर्तों के तहत दिया जाता है जैसा कि पहले आदेश संख्या 103-पीडीडी 2022 और आदेश संख्या 47-जेकेपीडीडी 2024 में अधिसूचित किया गया था। इस बार विभाग जिस एकमात्र अंतर पर प्रकाश डाल रहा है, वह है 31 मार्च, 2025 तक बकाया राशि पर ब्याज और अधिभार की 100 प्रतिशत छूट। देखने वाली बात यह है कि इस संबंध में जारी किए गए पहले के आदेशों की तरह, इस बार भी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि के बाद माफी का कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा। पहले के चलन को देखते हुए, जो लोग अपने बिजली बिलों का ईमानदारी से और नियमित आधार पर भुगतान नहीं करने के आदी हैं, वे आदेश के इस खंड को बिना ज्यादा ईमानदारी के लेने के लिए बाध्य हैं जैसा कि केंद्र शासित प्रदेश में हर कोई जानता है और इस योजना के अधिक रियायतों के साथ एक और विस्तार की उम्मीद कर रहा है क्योंकि सरकार इस मुद्दे से निपटने में असहाय प्रतीत होती है। जम्मू-कश्मीर में आम तौर पर कई लोगों की यह धारणा है कि बिना शुल्क चुकाए बिजली का इस्तेमाल करना एक आम बात है और यही वजह है कि बिजली विकास विभाग (पीडीडी) लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने में मुश्किलों का सामना कर रहा है। इस साल मार्च में आई रिपोर्टों से पता चला है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में सिर्फ़ सरकारी विभागों के 3517.90 करोड़ रुपये से ज़्यादा के बिजली बिल बकाया हैं। ऐसे क्षेत्र में, जहाँ सरकारी विभाग इतने गंभीर मुद्दे पर गंभीर नहीं हैं, आम आदमी की स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जो समय पर बिल न चुकाने के लिए खराब स्मार्ट मीटर, गलत बिलिंग आदि जैसे कई बहाने गढ़ रहा है। इससे पहले, पीडीडी विभाग ने बिजली का बकाया चुकाने में आनाकानी करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने का अभियान शुरू किया था, लेकिन बाहरी दबाव के कारण इस कड़े कदम को टाल दिया गया और विभाग ने अखबारों में बकाएदारों के नाम प्रकाशित करके दूसरा तरीका अपनाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस तरह पीडीडी के पास आखिरी उपाय के तौर पर अतिरिक्त सुविधाओं वाली एमनेस्टी योजना पर ही निर्भर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।

भारतीय हथकरघा: स्थायित्व के लिए परंपरा और नवाचार दोनों की आवश्यकता

गिरिराज सिंह, केंद्रीय वस्त्र मंत्री

हथकरघा क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है, जो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और 3.5 मिलियन से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करता है। स्थानीय बुनकरों द्वारा नैतिक रूप से निर्मित हथकरघा और दस्तकारी वस्त्र, बड़े पैमाने पर उत्पादित फास्ट फैशन का एक सार्थक विकल्प प्रस्तुत करते हैं। ऐसा करके, वे भारत की समृद्ध विरासत को आधुनिक विश्व के लिए एक व्यापक स्थिरता की कहानी में शामिल करते हैं।

टिकाऊ वस्त्र इको-सिस्टम के निर्माण के लिए ग्रामीण हथकरघा और हस्तशिल्प क्लस्टरों को सहायता देना महत्वपूर्ण है। ये क्लस्टर भारतीय शिल्पकला की उन जीवंत परम्पराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें परिवारों और समुदायों द्वारा पीढ़ियों से कायम रखा गया है। निजी क्षेत्र और सामाजिक उद्यमों ने इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने में सराहनीय भूमिका निभाई है। उनका कार्य पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों के साथ नवाचार, स्थानीय स्रोत, रि-साइक्लिंग और अप-साइक्लिंग तथा पारंपरिक प्रथाओं के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने तक फैला हुआ है। ये प्रयास सहयोग के माध्यम से कारीगर समुदायों को सशक्त बनाने, शिल्पकारों और डिजाइनरों के बीच साझेदारी बनाने, उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने और कारीगरों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। जापान के ओसाका में आयोजित विश्व एक्सपो 2025 और अमेरिका के सांता फे में आयोजित अंतरराष्ट्रीय लोक कला बाजार जैसे प्रतिष्ठित मंचों पर भारतीय शिल्पकारों की हालिया भागीदारी उनकी अनुकूलनशीलता और वैश्विक अपील को दर्शाती है।

भारत सरकार अनेक योजनाओं और पहलों के माध्यम से वस्त्र पारिस्थितिकी तंत्र (टेक्सटाइल इको-सिस्टम) का समर्थन करती है। इनमें कच्चे माल की खरीद, करघों और सहायक उपकरणों आदि की खरीद के लिए वित्तीय सहायता, महिला सशक्तिकरण के लिए प्रोत्साहन, कौशल विकास कार्यक्रम तथा पारंपरिक हथकरघों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु मार्केटिंग प्रयास शामिल हैं। पर्यावरण-अनुकूल और सर्कुलर प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने, जैविक कच्चे माल तक पहुँच में सुधार लाने और नैतिक प्रथाओं के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने पर भी ज़ोर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 'वोकल फॉर लोकल' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी पहलों ने हथकरघा बुनकरों के लिए अवसरों का काफी विस्तार किया है। 'कौशल भारत' और 'डिजिटल भारत' जैसे अन्य कार्यक्रम कारीगरों को अपने कौशल को अपग्रेड करने और अपने कार्यस्थलों से सीधे बड़े बाजारों तक पहुंचने में सक्षम बना रहे हैं।

इस क्षेत्र के विकास को बनाए रखने के लिए हथकरघा परंपराओं का दस्तावेजीकरण और संरक्षण भी समान रूप से आवश्यक है। वस्त्र मंत्रालय के नेतृत्व में डिजिटल संग्रह, भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष, पारंपरिक और समकालीन ज्ञान दोनों को संग्रहित करके इस उद्देश्य की पूर्ति करता है। यह मंच अनुसंधान डेटा, डिजाइनर

और कारीगर प्रोफाइल, एक वर्चुअल संग्रहालय और डिजिटल प्रदर्शनियां उपलब्ध कराता है, जिससे यह विद्वानों, शिक्षार्थियों और शिल्प उत्साही लोगों के लिए एक मूल्यवान संसाधन बन जाता है।

हथकरघा क्षेत्र को अधिक लक्ष्य-उन्मुख और लाभदायक बनाने के लिए व्यवसाय-केंद्रित रणनीति आवश्यक है। को-ऑप्टेक्स, बोयानिका अथवा टाटा ट्रस्ट द्वारा अन्तरान जैसे हथकरघा मार्केटिंग संगठनों की केस स्टडी से पता चलता है कि व्यवस्थित योजना, चाहे वह समितियों, सहकारी समितियों के प्रोत्साहन के माध्यम से हो अथवा गैर-लाभकारी संस्थाओं के साथ सहयोग के माध्यम से हो, हथकरघा बुनकरों की आय और आजीविका में महत्वपूर्ण सुधार ला सकती है।

इसे हासिल करने के कई तरीके हैं। पारंपरिक और आधुनिक, दोनों बाज़ारों के लिए नए डिज़ाइन विकसित करने के साथ-साथ पारंपरिक डिज़ाइनों को पुनर्जीवित करना, खासकर थीम-आधारित प्रदर्शनियों के ज़रिए, ग्राहकों को शिक्षित करने और माँग बढ़ाने में मदद कर सकता है। अंगवस्त्रम, वेष्टी और मुंडू जैसे उत्पादों को भी प्रासंगिक बने रहने के लिए विचारशील डिजाइन नवाचार की आवश्यकता होती है। वर्तमान आंकड़ों से पता चलता है कि केवल 22% हथकरघा बुनकर साड़ियां बनाते हैं और 19व अंगवस्त्रम और इसी तरह के उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे 59% ऐसे बुनकर बचते हैं जिन्हें घरेलू साज-सज्जा और वस्त्र सामग्री की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित और सक्रिय किया जा सकता है। आधुनिक रुचियों के अनुरूप ढलते हुए, भारतीय हथकरघा को परिभाषित करने वाले अद्वितीय क्षेत्रीय कौशल और तकनीकों को संरक्षित करना महत्वपूर्ण है। जैविक फाइबर, प्राकृतिक रंगों और टिकाऊ सामग्रियों के उपयोग से हथकरघा उत्पादों का मूल्य और आकर्षण और अधिक बढ़ सकता है।वस्त्र मंत्रालय संत कबीर और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार जैसे पुरस्कारों के माध्यम से बुनकरों के योगदान को सक्रिय रूप से मान्यता प्रदान कर रहा है और उन्हें पुरस्कृत कर रहा है। हाल के वर्षों में, नई श्रेणियां शुरू की गई हैं, जैसे कि महिला बुनकरों, जनजातीय कारीगरों, दिव्यांग बुनकरों, नवोन्मेषी उत्पादक समूहों और हथकरघा के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने वाले डिजाइनरों के लिए पुरस्कार। उल्लेखनीय है कि युवाओं को युवा बुनकर पुरस्कार भी दिया जाता है, जो 30 वर्ष से कम आयु के ऐसे कारीगरों को दिया जाता है, जिन्होंने पारंपरिक तकनीकों में निपुणता प्राप्त कर ली है तथा नवाचार अथवा उद्यमिता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हैं। ये पुरस्कार न केवल प्रतिष्ठित हैं बल्कि पारदर्शी और लोकतांत्रिक भी हैं, तथा इनके साथ नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र भी दिए जाते हैं। संत कबीर, राष्ट्रीय एवं राज्य पुरस्कार विजेताओं को आजीवन 8,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। इसका उद्देश्य हथकरघा के क्षेत्र में नवाचार, विशेष रूप से ऐसी तकनीकों और सौंदर्यबोध को बढ़ावा देना है, जिनकी मशीनों अथवा पावरलूमों द्वारा नकल नहीं की जा सकती है।

भारतीय हथकरघा उद्योग का स्थायित्व बनाए रखने के लिए परंपरा और नवाचार दोनों को अपनाने की आवश्यकता है। भारत कपास, रेशम, ऊन, जूट और नारियल के रेशों जैसे प्राकृतिक फाइबर से समृद्ध है, और यहाँ बाँस, केले के फाइबर, हेम्प और मिल्कवीड जैसी नई सामग्रियों की खोज तेज़ी से हो रही है।

कृषि अपशिष्ट की एक बड़ी मात्रा भी अभी तक पूरी तरह से उपयोग में नहीं आ पाई है। इस प्रचुरता के बावजूद, वास्तव में टिकाऊ उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर यार्न और वस्त्र प्रसंस्करण को मजबूत करने की अभी भी आवश्यकता है।

वस्त्र क्षेत्र में उद्यमों के सर्कुलर उत्पादन में तेजी आ रही है। वर्तमान समय में भारत की गहन भौतिक संस्कृति के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, यह केवल यार्न और फैब्रिक में ही नहीं, बल्कि परिधानों के सहायक उपकरणों में भी बढ रही है, जिनका पर्यावरणीय प्रभाव के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है। बचे हुए कपड़ों और धागों का उपयोग करके बनाए गए पुनर्चक्रित संग्रह लोकप्रिय हो रहे हैं, जो पारंपरिक, टिकाऊ प्रथाओं के पुनरुद्धार में योगदान दे रहे हैं। यह आंदोलन पर्यावरण के प्रति जागरूक फैशन की ओर एक व्यापक वैश्विक बदलाव को दर्शाता है।

आज, तेज़ी से बढ़ते शहरी प्रवास और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे के साथ, पारंपरिक बुनकर की अपने करघे पर भूमिका प्रतीकात्मक से कहीं ज्यादा बढ़ गई है, अब यह हरित तकनीक और सांस्कृतिक संरक्षण का एक सशक्त उदाहरण बन गई है। भारत की हथकरघा विरासत एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करती है जो पर्यावरण और शिल्प से जुड़े लोगों का सम्मान करती है और देश को ज़िम्मेदार एवं नैतिक फ़ैशन के क्षेत्र में अग्रणी बनाती है।

धराली आपदा: यह हम सभी के चेत जाने का समय है

डॉ. प्रियंका सौरभ

यह अजीब विडंबना है कि जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो हम सिर्फ़ मरने वालों पर शोक प्रकट करते हैं जबकि जिनके लालच, उपेक्षा और मूर्खता से वह आपदा आई, उन पर सवाल उठाने का साहस नहीं करते। एक नदी के बहाव में बहे मकानों और दुकानों को देखकर हम आंसू तो बहाते हैं, लेकिन क्या हम उस कुकर्म पर विचार करते हैं जिसने नदी की गोद में घर बनवा दिए? आज भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानों तक, हर जगह मनुष्य का प्रलोभन ही विनाश का बीज बन चुका है। हाल की घटनाएं- उत्तरकाशी, जोशीमठ, केदारनाथ, किन्नौर या हिमाचल की तबाही- सभी हमें याद दिलाती हैं कि जब मनुष्य अपने हित में प्रकृति की रेखाएं मिटा देता है, तो नदी, पहाड़, बादल और धरती एक दिन सबकुछ वापस ले लेते हैं।

मेरे घर के पास एक छोटा-सा रेस्तरां है। उसके नल से दिन-रात पानी टपकता रहता है। मैंने कई बार कहा, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ा। एक ढीला वॉशर बदलने से समस्या हल हो सकती है, लेकिन सौ-पचास रुपये की मरम्मत उनके लिए बेमतलब है। पानी बहता है, तो बहता रहे। क्या यह एक रेस्तरां तक सीमित लापरवाही है? बिल्कुल नहीं। यह प्रतीक है उस मानसिकता का जो कहती है- 卐जो हो रहा है, होने दो। हमें क्या फर्क पड़ता है?卐 इस सोच के कारण हर दिन लाखों लीटर पानी व्यर्थ जाता है, गाड़ियों से निकलती धुआं-संस्कृति जारी रहती है, कचरे में दम तोड़ती गायें खड़ी रहती हैं और हिमालय की छाती पर रिसॉर्ट्स उगते रहते हैं।

भारत का हिमालय क्षेत्र न सिर्फ़ भौगोलिक, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी हमारी धरोहर है परंतु अब वह पर्यटन का बाजार बन चुका है। पहाड़ों की आत्मा शांति थी, अब वह शोर में डूब चुकी है। दो दिन की छुट्टी मिलते ही लाखों लोग सेल्फी, शराब और शोरगुल की भूख लिए हिमालय पर टूट पड़ते हैं। वे वहां शांति खोजने नहीं जाते, बल्कि वहां भी उसी बाजार को बसाना चाहते हैं जिससे भागने का दावा करते हैं। रिसॉर्ट, होटल, रेस्टोरेंट, पार्किंग, रोड- हर जगह अतिक्रमण है। पहाड़ की सीमित सहन शक्ति की कोई चिंता नहीं। जिस ज़मीन को सदियों से पेड़ों ने थामा हुआ था, वहां अब कंक्रीट की मोटी परतें बिछ गई हैं। जब बरसात आती है, तो वह ज़मीन अपने भीतर पानी को नहीं समेट पाती- परिणामस्वरूप, वही जल वेग बनकर जान लेता है।

बादल फटते हैं, बाढ़ आती है और हम सोशल मीडिया पर दुख प्रकट करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या हम पूछते हैं कि उस बाढ़ ने रास्ता क्यों बदला? क्या वह प्राकृतिक था या उसे रोका गया था? नदियाँ सदियों से बहती आई हैं, उन्होंने अपने लिए रास्ता बनाया है। लेकिन जब हम घाटी में मकान बना लेते हैं, नदी के किनारे होटल ठोक देते हैं, तो वह नदी अपने रास्ते पर दोबारा लौटेगी ही। उत्तरकाशी की हालिया त्रासदी में पूरा गांव बह गया। लेकिन वह गांव पहाड़ों की गोद में नहीं था- वह नदी के पाट में बना था। यह कोई आस्था नहीं थी, यह लालच था। लालच कभी सुरक्षित नहीं रहता।

कठोर शब्द हैं, लेकिन सच यही है कि हम एक संवेदनहीन समाज में तब्दील हो चुके हैं। हम आपदाओं को रोकने के बजाय उनका इंतज़ार करते हैं ताकि मीडिया को दृश्य मिलें और सरकारें मुआवज़े का तमाशा कर सकें। हमने पर्यावरण को सिर्फ़ एक डॉक्युमेंट बना दिया है। नीति आयोग से लेकर नगर पंचायत तक, हर स्तर पर विकास का मतलब अतिक्रमण हो गया है। क्या यह दुखद नहीं कि पहाड़ों पर हो रही तबाही के बीच भी लोग डील खोज रहे हैं- 卐इस सीजन होटल सस्ते मिल जाएंगे卐? क्या हमने चेतना खो दी है? दिल्ली के डीएनडी फ्लाईओवर पर एक ऑटो चालक ने मुझे बताया कि उसने किसी को यमुना में प्लास्टिक की बोतल फेंकते देखा और बहुत दुखी हुआ। एक छोटे इंसान की बड़ी भावना! लेकिन क्या उस भीड़ को कोई समझा सकता है जो हर नदी, हर घाट, हर पहाड़ को बस 'घूमने की जगह' समझती है? हमारी आंतरिक यात्रा कभी शुरू ही नहीं होती। हम गाड़ी में बैठकर पहाड़ तक तो पहुंच जाते हैं लेकिन हमारे अंदर का इंसान वहीं के वहीं मैदान में पड़ा रहता है- लालची, उपभोगी और शोरगुल में डूबा। रेस्तरां का टपकता नल भले ही प्रतीकात्मक हो लेकिन यह उसी उपेक्षा का प्रतीक है जो हमने हिमालय और पर्यावरण के साथ बरती है। हम जिस संसाधन को रोज़ टपकने देते हैं- पानी, हवा, हरियाली, मिट्टी, हिमनद- वे एक दिन सूख जाएँगे। फिर नल नहीं टपकेगा, तब शायद उसमें से हवा भी न निकले। हम गाय को कचरा खिला कर भी उससे दूध की उम्मीद रखते हैं। हम पेड़ काट कर भी चाहते हैं कि बारिश हो। हम नदी को नाला बनाकर भी उससे आचमन की कामना करते हैं। क्या यह पाखंड नहीं है? अब समय मौन शोक का नहीं, चेतने का है। अगर हम नहीं चेते, तो अगली बार कोई नदी, कोई पहाड़, कोई हवा, कोई भूचाल हमें बख्शेगा नहीं। हमें पुनर्विचार करना होगा कि क्या हम अपने छोटे-छोटे प्रलोभनों को तिलांजलि देने को तैयार हैं? क्या हम पर्यावरणीय संतुलन को विकास की नींव बना सकते हैं? क्या हम 'घूमने' की जगह 'जुड़ने' की भावना से प्रकृति के पास जा सकते हैं?

मैं हिमालय नहीं जाती, न ही अपनी यात्राओं को पहाड़ों पर थोपती हूँ। यह कोई त्याग नहीं, सिर्फ़ समझदारी है। मैं विंध्याचल और अरावली की छोटी पहाड़ियों से संतुष्ट हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हिमालय की छाती पहले ही विदीर्ण है- उसे और कष्ट देना अब पाप है। जब तक हम विकास को सिर्फ़ भवनों और दुकानों में मापते रहेंगे, तब तक विनाश हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। हर बहता नल एक आपदा की दस्तक है। हर रिसता पहाड़, हर-भरा हुआ नदी का पाट, हर टूटता पुल हमें चेतावनी देता है कि प्रलोभन का परिणाम बहुत गहरा होता है। नदियाँ जब निगलने लगती हैं, तबतक देर हो चुकी होती है।

(लेखिका, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

धराली आपदा के सबक

डॉ. सुशील उपाध्याय

उत्तरकाशी की ताजा आपदा की गंभीरता को समझना हो तो 12 साल पहले की केदारनाथ त्रासदी को याद करना होगा। उत्तरकाशी जिले में कम से कम तीन जगहों पर बहुत कम अवधि में बादल फटे हैं और उनका परिणाम धराली गांव के एक बड़े हिस्से के गायब होने के रूप में सामने आया है। कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, इसका अभी अनुमान लगाना संभव नहीं लेकिन, यह संख्या बड़ी होगी, यह तय है।

उत्तराखंड में (पड़ोसी हिमाचल प्रदेश में भी) बादल फटना, भूस्खलन, पहाड़ दरकना-धंसना, नदियों का विकराल रूप धर लेना और अचानक ग्लेशियर फटना बेहद आम घटनाएं हो गई हैं। जो एक डरावना संकेत है। ऐसी हर एक घटना के बाद आमतौर पर प्रकृति को दोष दिया जाता है और भगवान से बचाने की गुहार लगाई जाती है, लेकिन इन दोनों से बात नहीं बनती। उत्तराखंड गठन के 25 साल में पहाड़ों में जितने व्यापक पैमाने पर निर्माण कार्य हुए हैं, हो रहे हैं और लोगों की आवाजाही बढ़ी है, वह चौंकाने वाली है। ये त्रासदियां संकेत दे रही हैं कि विकास के नाम पर प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उसकी कीमत अब लगातार चुकानी होगी। पहाड़ के आम जीवन में यह मान्यता है कि नदी अपने खोए हुए (बल्कि बिल्डरों द्वारा कब्जाए गए) रास्ते पर वापस जरूर आती है, भले ही 100 साल के अंतराल पर आए। धराली में नदी के प्रचंड वेग और उसके साथ बड़ी-बड़ी इमारतों, होटलों, घरों के बहने का दृश्य भयावह था लेकिन इसके लिए नदी बिल्कुल दोषी नहीं है। पहाड़ में प्राकृतिक आपदाएं नई नहीं हैं, ना ही इन्हें पूरी तरह रोका जा सकता है, लेकिन उनकी आवृत्ति और तीव्रता में बढ़ोतरी स्वाभाविक नहीं, बल्कि स्पष्ट रूप से मानवीय हस्तक्षेप का परिणाम है। अगर मोटे तौर पर देखें तो वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण भी हिमालयी क्षेत्र के मौसम में असामान्य परिवर्तन दिख रहे हैं। वर्षा का पैटर्न असंतुलित हो गया है। कभी महीनों तक सबकुछ सामान्य रहता है और फिर कुछ ही घंटों में मौसम तांडव करने लगता है। बादल फटना, जो पहले कभी कभार की घटना थी, अब हर बारिश में बार-बार सामने आ रही है। प्रदेश में विगत दशकों में अनियंत्रित और अनियोजित विकास ने भी परेशानी बढ़ाई है। केदारनाथ आपदा, नाचनी गांव आपदा, रैनी गांव आपदा, जोशीमठ का नीचे धंसना और धराली की आपदा एक भयावह संकेत कर रही है कि कुछ दशकों बाद उत्तराखंड में कई रूपकुंड (जहां आज भी नरकंकाल बिखरे हुए हैं) होंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के नाम पर जो ऑल वेदर रोड बनाई जा रही है, वह यहां के पहाड़ों के मिजाज के अनुरूप नहीं है। कच्चे पर्वतीय ढलानों को काटकर बनाई गई चौड़ी सड़कों ने पहाड़ों की आंतरिक संरचना को कमजोर किया है। इससे भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी हैं। सरकार यहां आने वाले लोगों के लिए सुविधाएं विकसित करने पर जोर दे रही है, लेकिन यह समझने की जरूरत महसूस नहीं की जा रही है कि उत्तराखंड और यहां का पहाड़ी इलाका बाहरी लोगों की अनियंत्रित आवाजाही के लायक नहीं है। लोग इतने बेपरवाह हैं कि वे इन दिनों भी बड़ी संख्या में चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं। पिछले सप्ताह ही सरकार ने करीब 5 हजार लोगों को केदारनाथ के रास्ते बमुश्किल सुरक्षित निकाला है। पर्यटकों की हर साल बढ़ती संख्या यहां के बुनियादी ढांचे पर दबाव पैदा कर रही है। नदी किनारे बसाहट और अवैज्ञानिक निर्माण ने भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा जैसी बड़ी नदियों से लेकर छोटी बरसाती नदियों तक के किनारों को होटलों, होमस्टे और बाजारों से ढक दिया है। यह निर्माण आर्थिक दृष्टि से भले लाभदायक लगे, लेकिन ये आपदा प्रबंधन के मानदंडों पर खरे नहीं उतरते। बाढ़, भूस्खलन या मलबे की घटना इन्हें पूरी तरह नष्ट कर देती है, जैसा धराली में देखने को मिला। इस परिप्रेक्ष्य में बड़ा सवाल यह कि क्या सरकार, प्रशासन और लोगों ने इन संकेतों से कुछ सीखा है? हर त्रासदी के बाद राहत और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया तो आरंभ होती है, लेकिन दीर्घकालिक समाधान और नीतिगत परिवर्तन नदारद रहते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि आपदाएं कुछ ठेकेदारों और परियोजना संचालकों के लिए लाभ का माध्यम बन जाती हैं। इन सभी घटनाओं ने यह भी स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड की आपदा प्रबंधन प्रणाली में खामियां हैं। अग्रिम चेतावनी, स्थानीय प्रशिक्षण, सुरक्षित स्थानों की पहचान जैसे बुनियादी प्रावधान अब भी अधूरे और अपर्याप्त दिख रहे हैं। धराली में लोगों को इतना अवसर भी नहीं मिला कि खुद को बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की ओर जा पाते यदि ग्रहण किया जा सके तो आज का सबक यही है कि हिमालयी राज्यों में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की स्पष्ट नीति बने। नदी किनारे निर्माण पर सख्त प्रतिबंध हो, सड़क निर्माण से पहले भू-वैज्ञानिक सर्वे के निष्कर्षों को स्वीकार किया जाए और बड़े प्रोजेक्ट्स के पर्यावरणीय प्रभावों को गंभीरता से लिया जाए। अन्यथा हम लाशें गिनते रह जाएंगे। उत्तराखंड की त्रासदियां साफ चेतावनी दे रही हैं कि यदि अब भी सबक नहीं लिया गया, तो यह क्षेत्र केवल धार्मिक पर्यटन का केंद्र नहीं, बल्कि पर्यावरणीय आपदाओं का स्थायी ठिकाना बन जाएगा। नीतिगत और व्यवस्थागत सुधार तथा इनका सही क्रियान्वयन न हुआ तो यकीन मानिए, भविष्य की त्रासदियां और भी भयावह होंगी।

आयरलैंड की ऐमी मैग्वायर को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाज़ी की मिली अनुमति

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने घोषणा की कि आयरलैंड की बाएं हाथ की स्पिनर ऐमी मैग्वायर को तत्काल प्रभाव से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाज़ी करने की अनुमति दे दी गई है। 18 वर्षीय मैग्वायर को फरवरी में अवैध गेंदबाज़ी एक्शन के चलते गेंदबाज़ी से निलंबित कर दिया गया था। उन्हें भारत के खिलाफ 10 जनवरी को राजकोट में खेले गए वनडे सीरीज़ के पहले मैच के दौरान संदिग्ध एक्शन के लिए रिपोर्ट किया गया था, जिसमें उन्होंने 8 ओवर में 57 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे। इसके बाद मैग्वायर ने अपने गेंदबाज़ी एक्शन में बदलाव किया और एक आईसीसी-मान्यता प्राप्त परीक्षण केंद्र में पुनर्मूल्यांकन करवाया। आकलन में यह पाया गया कि उनके नए एक्शन में कोहनी का मोड़ अब आईसीसी के नियमों के अनुसार 15 डिग्री की तय सीमा के भीतर है। इसके बाद उन्हें फिर से गेंदबाज़ी की अनुमति दे दी गई है।

महिला स्पीड चेस चैंपियनशिप 2025: पहले ही राउंड में बाहर हुईं आर. वैशाली

नई दिल्ली। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर. वैशाली को महिला स्पीड चेस चैंपियनशिप 2025 के पहले राउंड में ही हार का सामना करना पड़ा। उन्हें सोमवार को अमेरिकी इंटरनेशनल मास्टर एलिस ली ने 8-6 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। मैच की शुरुआत में वैशाली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5+1 सेक्शन में 3.5-0.5 की बढ़त बना ली थी, लेकिन 3+1 सेक्शन में एलिस ली ने जबरदस्त वापसी करते हुए लगातार चार मुकाबले जीत लिए। अंतिम 1+1 सेक्शन में भी उन्होंने 3-2 से बढ़त बनाई और मुकाबला अपने नाम किया। यह टूर्नामेंट ऑनलाइन खेला जा रहा है और इसमें कुल 16 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें आठ क्वालिफायर हैं जबकि आठ को सीधे आमंत्रित किया गया है। प्रतियोगिता की कुल इनामी राशि 75,000 अमेरिकी डॉलर है, जिसमें विजेता को 7,000 डॉलर मिलेंगे। भारत की दिव्या देशमुख इस टूर्नामेंट में अब एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बची हैं। हाल ही में फिडे वर्ल्ड कप जीतकर ग्रैंडमास्टर बनीं 19 वर्षीय दिव्या 11 अगस्त को चीनी जीएम लेई टिंगजी के खिलाफ पहला मुकाबला खेलेंगी।

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ने इंग्लैंड की आलोचना की, सकारात्मक क्रिकेट का मतलब लापरवाह क्रिकेट नहीं

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ग्रेग चैपल ने भारत के खिलाफ ड्रॉ हुई टेस्ट श्रृंखला के दौरान इंग्लैंड की आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने की रणनीति की आलोचना करते हुए कहा, 'सकारात्मक क्रिकेट का मतलब लापरवाह क्रिकेट नहीं है। चैपल ने अपने कॉलम में युवा भारतीय टीम की अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रशंसा की, वहीं इंग्लैंड के खिलाड़ियों, विशेषकर हैरी ब्रुक की आलोचना की, क्योंकि वे परिस्थितियों को समझने में विफल रहे। भारत के पूर्व मुख्य कोच चैपल ने कहा, 'इस श्रृंखला में इंग्लैंड का सफर उसके सामने चेतावनी पेश करता है। इसे प्रतिभाशाली लेकिन चंचल प्रकृति के हैरी ब्रुक ने मूर्त रूप दिया, जिनकी मैं पहले सार्वजनिक रूप से प्रशंसा कर चुका हूं।उन्होंने कहा, 'उनकी टाइमिंग बहुत अच्छी है। वह कई तरह के शॉट लगा सकते हैं। उनमें आत्मविश्वास है और बल्लेबाजी को सहज बनाने का दुर्लभ कौशल है। लेकिन क्रिकेट, विशेष रूप से टेस्ट क्रिकेट, केवल शॉट लगाने के बारे में नहीं है। यह निर्णय लेने के बारे में है। टेस्ट क्रिकेट में यह समझना जरूरी होता है कि कब आक्रामक होकर खेलना है और कब संयम बरतना है।

नीदरलैंड तीन टी20 मैचों के लिए करेगा बांग्लादेश का दौरा

ढाका। बांग्लादेश पहली बार द्विपक्षीय श्रृंखला में नीदरलैंड्स की मेजबानी करेगा, जिसमें दोनों टीमें तीन मैचों की टी20 श्रृंखला खेलेंगी। यह श्रृंखला 30 अगस्त से शुरू होगी और तीनों मैच सिलहट में खेले जाएंगे। नीदरलैंड की टीम 26 अगस्त को बांग्लादेश पहुंचेगी और श्रृंखला शुरू होने से पहले तीन दिन प्रशिक्षण लेगी। पहला टी20 मैच 30 अगस्त को, दूसरा और तीसरा मैच क्रमशः 1 और 3 सितंबर को होगा, ये सभी मैच सिलहट के एसआईसीएस स्टेडियम में खेले जाएंगे। यह श्रृंखला 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप से पहले बांग्लादेश के लिए महत्वपूर्ण तैयारी का काम करेगी। नीदरलैंड्स इससे पहले एक बार बांग्लादेश में खेल चुका है, 2014 टी20 विश्व कप के दौरान। दोनों टीमें एक-दूसरे के खिलाफ पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुकी हैं, जिनमें से चार में बांग्लादेश ने जीत हासिल की है। 2012 में नीदरलैंड ने दो मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के लिए बांग्लादेश की मेजबानी की थी, आगामी दौरे से पहले उनका एकमात्र द्विपक्षीय मुकाबला होगा। दोनों टीमें पिछली बार आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 में आमने-सामने हुई थीं, जहां बांग्लादेश ने 25 रनों से जीत हासिल की थी।

आईजीपीएल जैसी लीग युवाओं को न सिर्फ मंच देगी, बल्कि आर्थिक रूप से सहयोग भी करेगी :गगनजीत सिंह भुल्लर

एजेंसी

नई दिल्ली। अनुभवी भारतीय गोल्फर और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित गगनजीत सिंह भुल्लर ने इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग (आईजीपीएल) में एक आइकन खिलाड़ी के रूप में करार किया है। वह इस बहुप्रतीक्षित लीग में एक फ्रेंचाइजी टीम का नेतृत्व करेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भुल्लर ने आईजीपीएल को हाल के वर्षों की सबसे रोमांचक गोल्फ पहल बताया और इसमें भाग लेने के पीछे की वजहों को साझा किया। भुल्लर ने कहा, गोल्फ एक व्यक्तिगत खेल है, लेकिन जब भी मुझे देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है, मुझे टीम के रूप में खेलने में हमेशा आनंद आया है। 2006 के दोहा एशियाई खेलों में जब हमने रजत पदक जीता, वह अनुभव आज भी यादगार है।

भुल्लर ने कहा, लोगों को शायद यह अंदाजा नहीं होता कि गोल्फ एक बेहद महंगा खेल है। ऐसे में आईजीपीएल जैसी लीग युवाओं को न सिर्फ मंच देगी, बल्कि आर्थिक रूप से भी सहयोग करेगी। यह केवल शोपीस लीग नहीं है, बल्कि इसमें गंभीर प्रतिस्पर्धा और बड़ी इनामी राशि होगी। उन्होंने कहा, जो युवा खिलाड़ी अपने करियर की शुरुआत में हैं, उनके लिए इस तरह की लीग में हिस्सा लेकर पैसे कमाना और खुद के खेल में निवेश करना बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि जब संसाधन नहीं होते, तो शुरुआत में ही बहुत से खिलाड़ी पीछे रह जाते हैं। आईजीपीएल इस खाई को पाटने में मदद करेगा। उन्होंने कहा, ÷जब मुझे गोल्फ लीग की जानकारी मिली, तो मुझे लगा कि यही वो चीज़ है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। क्योंकि हम अक्सर टीम के रूप में नहीं खेल पाते। यह एक ऐसा पहलू था जो मेरे करियर में अधूरा सा लग रहा था।

आईजीपीएल भारत की पहली पेशेवर गोल्फ लीग होगी जिसमें पुरुष और महिला खिलाड़ी एक ही मंच पर खेलते नजर आएंगे। फ्रेंचाइजी आधारित इस लीग में क्षेत्रीय सर्किट्स भी होंगे, जिससे यह लीग न केवल खेल के प्रारूप को नया रूप देगी, बल्कि समावेशिता और एथलीट सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देगी। इस लीग से जुड़ी प्रमुख बातों में क्रिकेट के दिग्गज और गोल्फ प्रेमी युवराज सिंह का बतौर सह-मालिक और ब्रांड एंबेसडर होना और इंडियन गोल्फ यूनियन के साथ समझौता ज्ञापन साइन करना शामिल है। इससे यह लीग भारत में पुरुषों, महिलाओं और शौकिया गोल्फरों के लिए एक प्रमुख मंच बनने की दिशा में अग्रसर है। भुल्लर इस लीग को उभरती प्रतिभाओं को निखारने और आगे बढ़ाने का एक बड़ा अवसर मानते हैं। उन्होंने कहा, ÷जब मुझे टीम का कप्तान बनने का मौका मिला, तो मैंने सोचा कि मैं अगली पीढ़ी के गोल्फरों का मार्गदर्शन कर सकता हूं। यह जिम्मेदारी मुझे व्यक्तिगत रूप से भी बहुत उत्साहित करती है। शिव कपूर, गौरव घई और एसएसपी चौरसिया जैसे दिग्गजों की मौजूदगी से युवा खिलाड़ियों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उनका विकास तेज़ी से होगा। पहले संस्करण के आयोजन से पहले, आईजीपीएल का दौरा देश के विभिन्न शहरों में कराया जाएगा ताकि देशभर में गोल्फ को लेकर माहौल तैयार किया जा सके और प्रतिभावान खिलाड़ियों को लीग से जोड़ा जा सके।

सब-जूनियर पुरुष हॉकी राष्ट्रीय चैम्पियनशिप :उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीम सेमीफाइनल में

एजेंसी

चेन्नई। मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में चल रही 15वीं हॉकी इंडिया सब-जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैम्पियनशिप 2025 के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में उत्तर प्रदेश हॉकी, हॉकी पंजाब, हॉकी झारखंड और हॉकी मध्य प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अब सेमीफाइनल मुकाबलों में उत्तर प्रदेश हॉकी का सामना हॉकी पंजाब से, जबकि हॉकी झारखंड का मुकाबला हॉकी मध्य प्रदेश से होगा। ये दोनों मैच बुधवार को खेले जाएंगे।

उत्तर प्रदेश ने दर्ज की 4-1 से जीत: दिन के पहले क्वार्टर फाइनल में उत्तर प्रदेश हॉकी ने दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव हॉकी को 4-1 से हराया। उत्तर प्रदेश के लिए अली शाहरुख ने (6वें और 23वें मिनट में) दो गोल किए, जबकि राजभर प्रह्लाद (42फीसदी) और मोहम्मद आतिफ रेनी (58फीसदी) ने एक-एक गोल जोड़े। दादरा एवं नगर हवेली की ओर से कप्तान धीरज पाल (39फीसदी) ने टीम की ओर से एकमात्र गोल किया।

पंजाब ने रोमांचक मुकाबले में ओडिशा को हराया

दूसरे क्वार्टर फाइनल में हॉकी पंजाब ने हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा को कड़े मुकाबले में 4-3 से शिकस्त दी।ओडिशा के कप्तान मंदीप केरकेट्टा ने (10फीसदी, 27फीसदी, 41फीसदी) हैट्रिक लगाई, लेकिन पंजाब के अर्जुनदीप सिंह (14फीसदी), वरिंदर सिंह (39फीसदी), अनुराग सिंह (42फीसदी) और सुखदेव सिंह (58फीसदी) के गोलों ने टीम को जीत दिला दी।

यूएई त्रिकोणीय सीरीज के लिए अफगानिस्तान की 22 सदस्यीय प्रारंभिक टीम घोषित

एजेंसी

काबुल। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान और यूएई के खिलाफ आगामी त्रिकोणीय सीरीज के लिए 22 खिलाड़ियों की प्रारंभिक टीम घोषित कर दी है। टीम की कमान स्टार लेग स्पिनर राशिद खान को सौंपी गई है। इस टीम में रहमानुल्लाह गुरबाज़, फजलहक फारूकी, अजमतुल्लाह उमरजई और अनुभवी मोहम्मद नबी जैसे प्रमुख खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। त्रिकोणीय सीरीज की शुरुआत 29 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से होगी। इससे पहले अफगानिस्तान टीम दो हफ्तों के प्रशिक्षण शिविर में भाग लेगी। यह सीरीज अफगानिस्तान के लिए आगामी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी का अहम हिस्सा मानी जा रही है।

अफगानिस्तान की प्रारंभिक टीम : राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), सदीकुल्लाह अटल, वफिउल्लाह तारखिल, इब्राहिम जादरान, दरवेश रसूली, मोहम्मद इसहाक, मोहम्मद नबी, नंग्याल खारोती, शराफुद्दीन अशरफ, करीम जन्नत, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नैब, मुजीब जादरान, एएम ग़ज़नफ़र, नूर अहमद, फजलहक फारूकी, नवीन उल हक़, फरीद मलिक, सलीम साफ़ी, अब्दुल्लाह अहमदजई और बशीर अहमद।

कनेडियन ओपन 2025: ओसाका ने सेमीफाइनल में बनाई जगह, टॉसन ने कीज़ को हराया

एजेंसी

मॉन्ट्रियल। जापान की पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 और चार बार की ग्रैंड स्लैम विजेता नाओमी ओसाका ने कनाडियन ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली। उन्होंने 10वीं वरीयता प्राप्त एलीना स्वितोलिना को महज 6-2, 6-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को जारी रखा। सेमीफाइनल में अब ओसाका का सामना 16वीं वरीय क्लारा टॉसन से होगा, जिन्होंने दिन के पहले क्वार्टरफाइनल में छठी वरीयता प्राप्त मैडिसन कीज़ को 6-1, 6-4 से हराकर चौंका दिया। ओसाका, जो 2022 में मियामी ओपन के फाइनल के बाद पहली बार किसी डब्ल्यूटीए 1000 सेमीफाइनल में पहुंची हैं, 2023 में बेटी शाई के जन्म के लिए 15 महीने के ब्रेक के बाद टेनिस में लौटी हैं। वह अपने करियर का आठवां खिताब और 2021 ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद पहला खिताब जीतने की कोशिश कर रही हैं। इस बीच, बुधवार को खेले जाने वाले एक और सेमीफाइनल में, कनाडा की 18 वर्षीय विक्टोरिया म्बोको का मुकाबला नौवीं वरीय एलेना रायबाकिना (कजाखस्तान) से होगा। टोरंटो की रहने वाली म्बोको, जो पहली बार नेशनल बैंक ओपन के मुख्य ड्रॉ में खेल रही हैं, इस टूर्नामेंट के शानदार प्रदर्शन के चलते टॉप 50 रैंकिंग में प्रवेश करेंगी। उन्होंने टूर्नामेंट में टॉप सीड कोको गॉफ सहित पाँच उच्च वरीय खिलाड़ियों को हराया है।

भावुक टॉसन ने जीत अपने दादा को समर्पित की

क्लारा टॉसन ने अपनी जीत अपने दादा पीटर को समर्पित की। उन्होंने मैच के बाद कोर्ट पर भावुक होते हुए कहा, मैं आज उनके लिए जीतना चाहती थी। उन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया, टेनिस खेलने में मदद की, स्कूल से हर दिन प्रैक्टिस के लिए ले जाते थे।22 वर्षीय डेनमार्क की खिलाड़ी ने बताया कि उन्हें सोमवार सुबह अपने दादा के निधन की खबर मिली, ठीक एक दिन बाद जब उन्होंने विंबलडन चैंपियन और विश्व नंबर 3 इगा स्विएतेक को सीधे सेटों में हराया था। टॉसन ने टूर्नामेंट में अब तक एक भी सेट नहीं गंवाया है।

मैच में कीज़ की चूक

ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की विजेता मैडिसन कीज़ ने मैच की शुरुआत में दो ब्रेक पॉइंट गंवाए, जिसके बाद टॉसन ने पहला सेट लगातार पांच गेम जीतकर अपने नाम कर लिया। कीज़ ने माना कि उनका प्रदर्शन उम्मीद के अनुसार नहीं रहा। उन्होंने कहा, आज मेरा दिन नहीं था। उसने शानदार टेनिस खेला, बेहतरीन सर्व किया। मैं अलग-अलग रणनीति आज़माती रही, लेकिन वह हर चीज़ का जवाब देती रही।

कर्नाटक ने 41वीं सब-जूनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में मारी बाजी, मणिपुर रहा उपविजेता

एजेंसी

बेंगलुरु। बसवंगुड़ी एक्वाटिक सेंटर, बेंगलुरु में संपन्न हुई 41वीं सब-जूनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में मेजबान कर्नाटक ने कुल 104 अंकों के साथ ओवरऑल ट्रॉफी अपने नाम कर ली। मणिपुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 81 अंकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। व्यक्तिगत स्तर पर मणिपुर के कोइजाम अथोइबा सिंह ने 28 अंक अर्जित कर सर्वश्रेष्ठ पुरुष तैराक का खिताब जीता। वहीं, गोवा की पूर्वी रितेश नाइक ने 19 अंकों के साथ सर्वश्रेष्ठ महिला तैराक का गौरव हासिल किया।

प्रमुख स्पर्धाओं का विवरण:

100 मीटर बैकस्ट्रोक (बालक वर्ग): तमिलनाडु के ए.पी. आर्य सथार और मध्यप्रदेश के कृषिव दोशी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। अंततः आर्य ने 1:05.53 समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। कृषिव दोशी 1:05.74 पर रजत पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहे।

मणिपुर के हेमांशु नाहाकपम ने 1:08.90 के समय के साथ कांस्य पदक हासिल किया।

100 मीटर बैकस्ट्रोक (बालिका वर्ग): तमिलनाडु की अल्फिया एम और हरियाणा की सेरेना सरोहा के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। अंतिम क्षणों में अल्फिया ने तेजी दिखाई और 1:10.70 के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। सेरेना ने 1:11.84 पर रजत और महाराष्ट्र की अनिका गोपलानी ने 1:13.36 समय के साथ कांस्य पदक प्राप्त किया।

100 मीटर फ्रीस्टाइल (बालक वर्ग): मणिपुर के दो तैराकों – कोइजाम अथोइबा सिंह और हेमांशु नाहाकपम – के बीच रोमांचक रेस हुई। कोइजाम ने 58.59 सेकंड में गोल्ड जीता, जबकि हेमांशु 59.75 सेकंड में दूसरे स्थान पर रहे। तमिलनाडु के आर्य सथार ने 1:00.79 में रेस पूरी कर कांस्य पदक जीता।

100 मीटर फ्रीस्टाइल (बालिका वर्ग): कर्नाटक की स्तुति सिंह, महाराष्ट्र की अमतुल्लाह ढोलकवाला और गोवा की पूर्वी रितेश नाइक के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ। मध्य रेस के बाद यह मुकाबला पूर्वी और स्तुति के बीच सिमट गया, जिसमें पूर्वी ने 1:04.40 समय के साथ स्वर्ण पर कब्जा जमाया। स्तुति 1:04.49 पर रजत और अमतुल्लाह 1:05.30 समय के साथ तीसरे स्थान पर रहीं।

डीपीएल 2025:सुयश शर्मा और शौर्य मलिक की घातक गेंदबाजी से आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने पुरानी दिल्ली-6 को 82 रनों से रौंदा

एजेंसी

नई दिल्ली। अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) सीजन-2 के छठे मुकाबले में आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरानी दिल्ली-6 को 82 रनों से करारी शिकस्त दी। गेंदबाजी में सुयश शर्मा और शौर्य मलिक ने कमाल दिखाया, जिन्होंने विपक्षी टीम की कमर तोड़ दी। 149 रनों का बचाव करते हुए आउटर दिल्ली के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बना लिया। युवा लेग स्पिनर सुयश शर्मा ने पावरप्ले में ही तहलका मचा दिया। उन्होंने समर्थ सेठ (18), कप्तान वंश बेदी (1) और प्रणव पंत (6) को आउट कर शीर्ष क्रम को झकझोर दिया। इसके बाद आरुष मल्होत्रा (5) भी जल्दी चलते बने, जिससे स्कोर मात्र 31/4 हो गया। इसके बाद रनआउट के चलते देव लाकड़ा (5) का विकेट गिरा। अगले ही ओवर में तेज गेंदबाज शौर्य मलिक ने दो गेंदों में युग गुप्ता (1) और एकांश डोबाल (0) को पवेलियन भेजकर मैच पूरी तरह आउटर दिल्ली की झोली में डाल दिया। शौर्य ने फिर आयुष सिंह (4) को एलबीडब्ल्यू कर पुरानी दिल्ली को 50/8 की शर्मनाक स्थिति में पहुंचा दिया। इसके बाद तो बचाव की कोई गुंजाइश नहीं बची। सुयश ने राजनीश दादर (5) को आउट कर अपना चौथा विकेट लिया, और अंत में हर्ष त्यागी ने ललित यादव (20) को आउट कर पुरानी दिल्ली 6 की पारी को 14.3 ओवर में सिर्फ 66 रनों पर समेट दिया। इससे पहले, आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी और तेज शुरुआत की। प्रियांश आर्य (16) और सनत सांगवान (26) ने आक्रामक अंदाज में रन बटोरे।

वेस्ट दिल्ली लायंस ने साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज़ को 8 विकेट से हराया, अंकित कुमार और कृष यादव की धमाकेदार साझेदारी

एजेंसी

नई दिल्ली। अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) 2025 के दूसरे सीज़न के मुकाबले में वेस्ट दिल्ली लायंस ने साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज़ को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। इस जीत के हीरो रहे सलामी बल्लेबाज़ अंकित कुमार और विकेटकीपर-बल्लेबाज़ कृष यादव, जिन्होंने टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। 186 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्ट दिल्ली लायंस की टीम की शुरुआत बेहद धमाकेदार रही। अंकित और कृष ने पहले विकेट के लिए मात्र 14 ओवरों में 158 रनों की तूफानी साझेदारी की, जिसने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। कृष यादव ने 42 गेंदों पर 67 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें शानदार स्ट्रोक्स और तेज़ रनिंग शामिल रही। वहीं, अंकित कुमार दुर्भाग्यवश शतक से चूक गए और 46 गेंदों में 96 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए। उनकी इस पारी में 11 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के शामिल थे।इससे पहले, साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज़ ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए अच्छी शुरुआत की। ओपनर कुनवर बिधूड़ी (27 गेंदों में 42 रन) और सुमित माथुर (29 गेंदों में 33 रन) ने पहले विकेट के लिए 74 रन जोड़े। कप्तान आयुष बडोनी ने भी 25 गेंदों में 48 रनों की अहम पारी खेली। हालांकि, मिडल ओवर्स के बाद सुपरस्टार्ज़ की पारी बिखर गई और टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही। अंततः टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 185 रन ही बना सकी। वेस्ट दिल्ली लायंस के गेंदबाज़ों ने डेथ ओवर्स में शानदार गेंदबाज़ी की। अनिरुद्ध चौधरी ने 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट झटके। वहीं, मनन भारद्वाज ने 2/23 और हृतिक शौकीन ने 1/16 का योगदान दिया।

लीग्स कप 2025: चोट के कारण पुमास यूनाम के खिलाफ इंटर मियामी के मैच से बाहर रहेंगे लियोनेल मेसी

एजेंसी

मियामी। इंटर मियामी को लीग्स कप 2025 के अहम मुकाबले में बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी पुमास यूनाम के खिलाफ होने वाले ग्रुप स्टेज मुकाबले से बाहर हो गए हैं। टीम के कोच जेवियर माशेरानो ने इसकी पुष्टि की। माशेरानो ने बताया कि मेसी को पिछले शनिवार नैकैक्सा के खिलाफ मियामी की जीत के दौरान दाहिनी जांघ के ऊपरी हिस्से में हल्की मांसपेशियों की चोट लगी है।

माशेरानो ने पत्रकारों से कहा, बुरी खबर के बीच अच्छी बात ये है कि मेसी आमतौर पर काफी तेजी से चोट से उबरते हैं,लेकिन साफ है कि वो कल के मैच के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि उनकी रिकवरी कैसी रहती है।

मेसी इस सीजन एमएलएस में सबसे ज्यादा 18 गोल कर चुके हैं और 2023 में इंटर मियामी को लीग्स कप खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभा चुके हैं। इंटर मियामी को लीग्स कप के क्वार्टरफाइनल में जगह बनाने के लिए पुमास यूनाम के खिलाफ यह मुकाबला हर हाल में जीतना जरूरी है। अगर टीम नॉकआउट चरण में पहुंचती है, तो मेसी के पास वापसी के लिए लगभग दो हफ्तों का समय होगा।इंटर मियामी का अगला एमएलएस मुकाबला रविवार को ओरलैंडो के खिलाफ खेला जाएगा।

विल ओ'रूर्के ज़िम्बाब्वे टेस्ट से बाहर, बेन लिस्टर को टीम में जगह

एजेंसी

बुलावायो। न्यूज़ीलैंड के तेज़ गेंदबाज़ विल ओ'रूर्के पीठ की चोट के कारण ज़िम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। न्यूज़ीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने इस बात की पुष्टि की। उनकी जगह बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ बेन लिस्टर को टीम में शामिल किया गया है। लिस्टर अब तक टेस्ट डेब्यू नहीं कर पाए हैं और इस सीरीज़ के लिए उन्हें कवर के तौर पर बुलाया गया है। ओ'रूर्के ने ज़िम्बाब्वे के खिलाफ पहले टेस्ट में हिस्सा लिया था, जहां तीसरे दिन खेल के दौरान उन्हें पीठ में अकड़न महसूस हुई थी। उन्होंने उस मुकाबले में कुल 23 ओवर फेंके थे और 3 विकेट झटके थे। पहले टेस्ट में न्यूज़ीलैंड ने ज़िम्बाब्वे को नौ विकेट से करारी शिकस्त दी थी। अब टीम दूसरा टेस्ट जीतकर दो मैचों की सीरीज़ में क्लीन स्वीप करना चाहेगी। दूसरा टेस्ट 7 अगस्त से बुलावायो के क्वींस क्रिकेट क्लब में शुरू होगा।

कनाडियन ओपन 2025: टेलर फ्रिट्ज़ और बेन शेल्टन के बीच ऑल-अमेरिकन सेमीफाइनल मुकाबला तय

एजेंसी

टोरंटो। टेलर फ्रिट्ज़ और बेन शेल्टन ने कनाडियन ओपन 2025 के क्वार्टरफाइनल में जीत दर्ज कर ऑल-अमेरिकन सेमीफाइनल की नींव रख दी है। यह पिछले 15 वर्षों में पहली बार है जब किसी एटीपी मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में दो अमेरिकी खिलाड़ी आमने-सामने होंगे। दूसरी वरीयता प्राप्त फ्रिट्ज़ ने छठी वरीयता प्राप्त रूस के आंद्रे रुब्लेव को 6-3, 7-6 (4) से हराया। फ्रिट्ज़ ने मुकाबले में कुल 20 ऐस लगाए, जिनमें अंतिम अंक पर लगाया गया ऐस निर्णायक साबित हुआ। इसके बाद चौथे वरीय शेल्टन ने ऑस्ट्रेलिया के नौवें वरीय एलेक्स डी मिनॉर को 6-3, 6-4 से मात दी। 22 वर्षीय शेल्टन ने पहली बार किसी एटीपी मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। फ्रिट्ज़ और शेल्टन के बीच यह ऐतिहासिक सेमीफाइनल मुकाबला आज खेला जाएगा। इससे पहले आखिरी बार 2010 में एंडी रोडिक और मार्डी फिश के बीच सिनसिनाटी में ऐसा ऑल-अमेरिकन सेमीफाइनल खेला गया था। होने वाला दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त जर्मनी के एलेक्ज़ेंडर ज्वेरेव और 11वीं वरीयता प्राप्त रूस के करेन खाचानोव के बीच होगा। ज्वेरेव 2017 में मॉन्ट्रियल में यह खिताब जीत चुके हैं। टूर्नामेंट का फाइनल गुरुवार को खेला जाएगा। 27 वर्षीय फ्रिट्ज़ ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाते हुए पहले गेम में तीन ऐस लगाए और अगले आठ अंक जीतते हुए रुब्लेव की सर्विस तोड़ी। उन्होंने पहले सेट में 4-1 की बढ़त हासिल करते हुए आसानी से सेट अपने नाम किया। फ्रिट्ज़, जो वर्तमान में एटीपी रैंकिंग में चौथे स्थान पर हैं और पिछले साल यूएस ओपन फाइनल में विश्व नंबर 1 यानिक सिनर से हार गए थे, अब अपने करियर का 11वां एटीपी टूर खिताब और दूसरा मास्टर्स 1000 खिताब जीतने की ओर अग्रसर हैं। दूसरे सेट में फ्रिट्ज़ ने 4-4 की बराबरी पर रुब्लेव की सर्विस तोड़ी, लेकिन रुसी खिलाड़ी ने तुरंत वापसी की और 6-5 की बढ़त ली। हालांकि, फ्रिट्ज़ ने सेट को टाईब्रेक में ले जाकर जीत दर्ज की। गौरतलब है कि इस बार कई शीर्ष खिलाड़ियों जैसे सिनर, जैक ड्रेपर (नंबर 5), नोवाक जोकोविच (नंबर 6) और कार्लोस अल्कराज (नंबर 2) ने इस टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया था। अल्कराज ने विंबलडन सेमीफाइनल में फ्रिट्ज़ को हराया था।

रुब्लेव, जो पिछले साल मॉन्ट्रियल में खेले गए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पोपिरिन से हार गए थे, इस बार चौथे दौर में ही बाहर हो गए। 27 वर्षीय यह खिलाड़ी विंबलडन और फ्रेंच ओपन के चौथे दौर तक पहुंचे थे।

स्टॉक मार्केट में बीडी इंडस्ट्रीज की फीकी एंट्री, सीमित दायरे में हो रहा है कारोबार

एजेंसी

नई दिल्ली। रोटेशनली मोल्डेड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी बीडी इंडस्ट्रीज के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में सपाट स्तर पर मामूली बढ़त के साथ एंट्री हुई। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 108 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 90 पैसे की बढ़त के साथ इसकी लिस्टिंग 108.90 रुपये के स्तर पर हुई। लिस्टिंग के बाद से ही ये शेयर सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। सुबह 11:30 बजे तक कारोबार होने के बाद कंपनी के शेयर 108.25 रुपये के स्तर ट्रेड कर रहे थे। इस तरह अभी तक के कारोबार में कंपनी के आईपीओ निवेशक सिर्फ 0.23 प्रतिशत के मुनाफे में हैं। बीडी इंडस्ट्रीज का 45.36 करोड़ रुपये का आईपीओ 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से फीका रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 1.81 गुना सब्सक्राइब हो सका था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 1.27 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इसी तरह नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 3.66 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 1.32 गुना सब्सक्राइब हुआ था।

आरबीआई ने रेपो रेट को 5.50 फीसदी पर रखा बरकरार, महंगाई दर का अनुमान घटाया

मुंबई/नई दिल्?ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने नीतिगत दर रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने रेपो रेट को 5.50 फीसदी पर बरकरार रखा है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर अनुमान को 6.5 फीसदी पर यथावत रखा है। वहीं, खुदरा महंगाई दर का अनुमान घटाकर 3.1 फीसदी कर दिया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को यहां मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की 4 से 6 अगस्त तक चली तीन दिवसीय समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए इसकी घोषणा की। संजय मल्होत्रा ने कहा, ''एमपीसी ने नीतिगत दर रेपो रेट को 5.5 फीसदी पर बरकरार रखने का फैसला किया है।'' इसका मतलब है आरबीआई आर्थिक स्थिति के हिसाब से नीतिगत दर में समायोजन को लेकर लचीला बना रहेगा। संजय मल्होत्रा ने बताया कि आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर के अनुमान को 6.5 फीसदी पर बरकरार रखा है। वहीं, चालू वित्त वर्ष के लिए खुदरा महंगाई दर के अनुमान को घटाकर 3.1 फीसदी कर दिया गया है, जबकि पहले रिजर्व बैंक ने इसके 3.7 फीसदी पर रहने का अनुमान जताया था।

शेयर बाजार में एनएसडीएल की मजबूत शुरुआत, 10 प्रतिशत प्रीमियम के साथ लिस्टिंग

नई दिल्ली। डिपॉजिटरी सर्विसेज मुहैया कराने वाली कंपनी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में जोरदार एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को खुश कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 800 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई पर 10 प्रतिशत प्रीमियम के साथ इसकी लिस्टिंग 880 रुपये के स्तर पर हुई। लिस्टिंग के बाद लिवाली शुरू हो जाने के कारण एनएसडीएल के शेयरों की चाल में तेजी आ गई। सुबह 11 बजे तक कारोबार होने के बाद एनएसडीएल के शेयर 899 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे थे। इस तरह अभी तक के कारोबार में ही कंपनी के आईपीओ निवेशकों को 12.38 प्रतिशत का मुनाफा हो चुका है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड का 4,011.60 करोड़ रुपये का आईपीओ 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 41.02 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 103.97 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इसी तरह नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 34.98 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 7.76 गुना और एंप्लॉयीज के लिए रिजर्व पोर्शन 15.39 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ के तहत कोई नया शेयर नहीं जारी हुआ है।

स्टॉक मार्केट में श्री लोटस डेवलपर्स की मजबूत शुरुआत, फायदे में रहे आईपीओ निवेशक

नई दिल्ली। मुंबई में रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज बनाने वाली कंपनी श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियल्टी के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में मजबूत शुरुआत की। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 150 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई पर इसकी एंट्री 179.10 रुपये के स्तर पर और एनएसई पर 178 रुपये के स्तर पर हुई। इस तरह ये शेयर करीब 19 प्रतिशत का लिस्टिंग गेन हासिल करने में सफल रहा। लिस्टिंग के बाद लिवाली शुरू हो जाने के कारण कंपनी के शेयर में और तेजी आ गई। सुबह 11 बजे तक कारोबार होने के बाद श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियल्टी के शेयर 188.23 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे थे। इस तरह अभी तक के कारोबार में ही कंपनी के आईपीओ निवेशकों को 25.80 प्रतिशत का मुनाफा हो चुका है।

जनधन योजना ने वित्तीय सेवाओं को गरीब लोगों तक पहुंचाया : पीएमओ

एजेंसी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) ने बैंकों और बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों के बीच की खाई को पाटकर, सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देकर सबसे गरीब लोगों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को पूरी तरह से बदल दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक आर्टिकल साझा किया, जिसमें बताया गया कि किस प्रकार एक सोशल वेलफेयर स्कीम के रूप में प्रधानमंत्री जन धन योजना ने 11 वर्ष पूरे होने पर सबसे गरीब लोगों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को बदल दिया है। आर्टिकल में कहा गया कि अगस्त 2014 में पीएमजेडीवाई की शुरुआत, बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि इससे बैंक में बेसिक सेविंग्स अकाउंट खोलने की सुविधा मिली है,

साथ ही रुपे डेबिट कार्ड और ओवरड्राफ्ट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हुई हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि अब तक पीएमजेडीवाई के तहत 55.90 करोड़ से ज्यादा खाते खोले जा चुके हैं। सरकार ने वित्तीय समावेशन को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की हैं कि बेसिक बैंकिंग सर्विसेज तक पहुंच से औपचारिक वित्तीय प्रणाली में सार्थक भागीदारी सुनिश्चित हो, जिसमें लोन तक पहुंच भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत 35.13 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 53.85 करोड़ लोन स्वीकृत किए जा चुके हैं। पीएमएमवाई सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 20 लाख रुपए तक का जमानत-मुक्त लोन प्रदान करता है, जिससे स्वरोजगार और आय सृजन संभव होता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों, रेहड़ी-पटरी वालों, कारीगरों और अन्य सूक्ष्म उद्यमों के लिए लोन पहुंच का विस्तार करने के उद्देश्य से स्टैंड-अप इंडिया (एसयूपीआई), प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), प्रधानमंत्री विश्वकर्मा और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) जैसी समर्पित योजनाएं लागू की गई हैं। क्रेडिट असिसमेंट फ्रेमवर्क से वंचित व्यक्तियों के लिए लोन मूल्यांकन ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार टेक्नोलॉजी और वैकल्पिक डेटा स्रोतों का लाभ उठा रही है।स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के उधारकर्ताओं और किसानों एवं हाशिए के समुदायों सहित ग्रामीण आबादी के क्रेडिट असिसमेंट में सहायता के लिए एक ग्रामीण क्रेडिट स्कोर की घोषणा की गई है। इस पहल से लोन निर्णयों की गुणवत्ता और निष्पक्षता में वृद्धि होने और ग्रामीण क्षेत्रों में औपचारिक लोन की बेहतर पहुंच होने की उम्मीद है।

मेहुल कलर्स की स्टॉक मार्केट में मजबूत शुरुआत, लिस्टिंग के बाद शेयरों में आई और तेजी

एजेंसी

नई दिल्ली। देश में मास्टरबैच और पिगमेंट्स को बनाने और उसकी सप्लाई करने वाली कंपनी मेहुल कलर्स एंड मास्टरबैचेज के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में जोरदार एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को खुश कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 72 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर 18.06 प्रतिशत प्रीमियम के साथ इसकी लिस्टिंग 85 रुपये के स्तर पर हुई। लिस्टिंग के बाद लिवाली शुरू हो जाने के कारण थोड़ी देर में ही ये शेयर उछल कर 89.25 रुपये अपर सर्किट लेवल पर आ गया। हालांकि थोड़ी देर बाद ही मुनाफा वसूली के चक्कर में हुई बिकवाली के कारण अपर सर्किट ब्रेक हो गया। दोपहर 12 बजे तक का कारोबार होने के बाद कंपनी के शेयर 86.50 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे थे। इस तरह पहले दिन के पहले सत्र के कारोबार में ही कंपनी के आईपीओ निवेशकों को 20.14 प्रतिशत का मुनाफा हो गया है। मेहुल कलर्स एंड मास्टरबैचेज का 21.66 करोड़ रुपये का आईपीओ 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 7.50 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ के तहत 30,08,000 नए शेयर जारी किए गए हैं। आईपीओ के जरिये जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लगाने, वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी। आईपीओ से एक दिन पहले कंपनी ने 29 जुलाई 2025 को एंकर निवेशकों से 6.15 रुपये करोड़ जुटाए थे। इसके लिए 8.54 लाख शेयरों का आवंटन 72 रुपये के भाव पर 5 प्रमुख एंकर निवेशकों को किया गया था।

शेल कंपनियों को पैसे भेजने से लेकर रिश्वत देने तक, ईडी ने लोन घोटाले पर अनिल अंबानी से पूछे कई सवाल

एजेंसी

नई दिल्ली। रिलायंस समूह (आरएएजीए कंपनियों) के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अनिल अंबानी से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में 17,000 करोड़ रुपए के बैंक लोन घोटाले को लेकर पूछताछ की। इस पूछताछ में ईडी की ओर से अनिल अंबानी से कई सवाल पूछे गए, जिसमें क्या लोन शेल कंपनियों को भेजे गए थे?, क्या पैसा राजनीतिक दलों को दिया गया? और क्या आपने किसी अधिकारी को रिश्वत दी? आदि शामिल थे। रिपोर्ट्स के अनुसार, रिलायंस समूह (आरएएजीए कंपनियों) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुबह-सुबह अपने आवास से राष्ट्रीय राजधानी स्थित ईडी मुख्यालय के लिए निकले थे। ईडी ने अनिल अंबानी को उनके समूह की कंपनियों के खिलाफ करोड़ों रुपए के कथित बैंक लोन घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले की चल रही जांच के तहत पूछताछ के लिए तलब किया था और उन्हें 5 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी स्थित

ईडी मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया था। जांचकर्ता इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि पिछले एक दशक में उनके समूह की कंपनियों द्वारा लिए गए लोन का उपयोग उनके द्वारा तय उद्देश्यों के लिए किया गया था या जानबूझकर उनका दुरुपयोग किया गया था। यह मामला अनिल अंबानी के रिलायंस समूह की कई कंपनियों से जुड़ा है, जिनमें रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस कम्युनिकेशंस शामिल हैं। जांच का एक हिस्सा 2017 और 2019 के बीच यस बैंक द्वारा दिए गए लगभग 3,000 करोड़ रुपए के लोन के कथित दुरुपयोग से संबंधित है। दूसरा हिस्सा रिलायंस कम्युनिकेशंस से जुड़े 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के एक बहुत बड़े घोटाले से जुड़ा है। पिछले हफ्ते, प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल अंबानी के रिलायंस समूह से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी पूरी की। जांचकर्ताओं ने मुंबई और दिल्ली में कई जगहों से बड़ी संख्या में दस्तावेज, हार्ड ड्राइव और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए। ये छापे यस बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में धन शोधन की जांच के एक हिस्से के रूप में शुरू हुए थे। ईडी, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के साथ मिलकर, धन के दुरुपयोग, लोन धोखाधड़ी और धन शोधन सहित वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच कर रही है।

कम ब्याज दरें रियल एस्टेट के लिए बनीं वरदान, अगली MPC बैठक से भी बड़ी उम्मीदें

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की आगामी बैठक से रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ी उम्मीदें हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस साल फरवरी से जून के बीच रेपो रेट में कुल 1फीसदी की कटौती ने हाउसिंग सेक्टर को नई गति दी है।

होम लोन की दरों में कमी से न केवल घर खरीदना अधिक वहन योग्य हुआ है, बल्कि खरीदारों का भरोसा भी बढ़ा है। रियल एस्टेट के दिग्गजों ने मुद्रास्फीति के नियंत्रण में होने का हवाला देते हुए रेपो रेट में एक और 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की संभावना जताई है। उनका मानना है कि यह कटौती अर्थव्यवस्था में खपत को बढ़ावा देगी और रियल एस्टेट सेक्टर को और मजबूत करेगी। प्रदीप अग्रवाल, फाउंडर और चेयरमैन, सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया) लिमिटेड, ने कहा कि मुद्रास्फीति ररूद्ध के लक्ष्य से काफी नीचे है, इसलिए रेपो रेट में लगातार चौथी कटौती की गुंजाइश है। उन्होंने कहा कि इससे होम लोन और सस्ते होंगे और ग्राहक जल्दी घर खरीदने का फैसला ले पाएंगे। जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जश पंचमिया ने कहा कि रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती पूरी अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत होगी, क्योंकि मुद्रास्फीति अपने छह साल के न्यूनतम स्तर पर है। कृष्णा ग्रुप एवं क्रिसुमी कॉरपोरेशन के चेयरमैन अशोक कपूर ने भी इसी बात पर जोर दिया और कहा कि अब तक की कटौती ने होम लोन की दरों को कम कर उपभोक्ता मांग को बढ़ाया है। एक और कटौती से यह गति और बढ़ेगी। एंड्रोमेडा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के को-सीईओ राउल कपूर ने बताया कि भू-राजनीतिक तनाव कम होने और घरेलू अर्थव्यवस्था में मजबूती के संकेत को देखते हुए 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की संभावना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि त्योहारों के सीजन में इसका फायदा मिलेगा। साया ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास भसीन ने कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि आरबीआई रेट कट साइकिल को जारी रखेगा, जिससे होम लोन और किफायती बनेंगे और होमबायर्स की लोन पात्रता में सुधार होगा। बेडरवाल ग्रुप के सीएमडी सुशील बेडरवाल ने कहा कि 100 बेसिस पॉइंट की कटौती से खासतौर पर किफायती और मिड-इनकम हाउसिंग सेगमेंट के खरीदारों को राहत मिली है, और वह आगामी बैठक में 25 बेसिस पॉइंट की और कटौती की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि बैंक इस कटौती का लाभ जल्द से जल्द ग्राहकों तक पहुंचाएंगे।

एटीएम से 500 रुपए के नोटों की सप्लाई बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं : केंद्र

एजेंसी

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने दोहराया कि 500 रुपए के नोटों की सप्लाई बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और एटीएम से 100 रुपए और 200 रुपए के नोटों के साथ-साथ 500 रुपए के नोट भी निकलते रहेंगे। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि किसी विशेष मूल्यवर्ग के नोटों की छपाई का निर्णय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के परामर्श से लेती है ताकि जनता की लेन-देन संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए मूल्यवर्ग मिश्रण बनाए रखा जा सके। राज्य मंत्री ने कहा, आरबीआई ने सूचित किया है कि बार-बार इस्तेमाल होने वाले बैंक नोटों तक जनता की पहुंच बढ़ाने के अपने प्रयास के तहत, 28 अप्रैल, 2025 को 'एटीएम के माध्यम से 100 रुपए और 200 रुपए के बैंक नोटों का वितरण' शीर्षक से एक परिपत्र जारी किया गया है, जिसमें

सभी बैंकों और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों (डब्ल्यूएलएओ) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि उनके एटीएम नियमित रूप से 100 रुपए और 200 रुपए के बैंक नोट वितरित करें। लगभग 75 प्रतिशत एटीएम 30 सितंबर तक कम से कम एक कैसेट से 100 रुपए या 200 रुपए के बैंक नोट वितरित करेंगे। इसके अलावा, लगभग 90 प्रतिशत एटीएम 31 मार्च, 2026 तक कम से कम एक कैसेट से 100 रुपए या 200 रुपए के बैंक नोट वितरित करेंगे। सरकार ने एक वॉट्सऐप मैसेज को 'असत्य' करार दिया, जिसमें दावा किया गया था कि आरबीआई ने बैंकों को 30 सितंबर तक एटीएम के माध्यम से 500 रुपए के नोट जारी करना बंद करने का आदेश दिया है। सरकार ने कहा कि ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। इस भ्रामक संदेश में यह भी दावा किया गया था कि 90 प्रतिशत एटीएम 31 मार्च, 2026 तक 500 रुपए के नोट जारी करना बंद कर देंगे और 75 प्रतिशत एटीएम 30 सितंबर तक ऐसा कर देंगे। इसके अतिरिक्त, इसमें लोगों को अपने 500 रुपए के नोट समाप्त करने की सलाह दी गई थी और यह भी कहा गया था कि भविष्य में एटीएम के माध्यम से केवल 100 और 200 रुपए के नोट ही उपलब्ध होंगे। इस मैसेज पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रेस सूचना ब्यूरो की फैक्ट चेक यूनिट ने कहा कि आरबीआई ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है और 500 रुपए के नोट अभी भी वैध मुद्रा हैं। एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया कि व्यापक रूप से साझा किया जा रहा यह दावा असत्य है और लोगों को ऐसी झूठी सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी गई। फैक्ट चेक यूनिट ने आधिकारिक स्रोतों से किसी भी फाइनेंशियल अपडेट की पुष्टि करने के महत्व पर जोर दिया और आगाह किया कि ऐसे संदेशों का उद्देश्य धोखा देना होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने 34,000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में धीरज वधावन की जमानत रद्द की

एजेंसी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में 34,000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी धीरज वधावन को मिली जमानत को रद्द कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा चिकित्सा आधार पर दी गई जमानत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करते हुए वधावन को दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान सर जे.जे. अस्पताल, मुंबई के डॉक्टरों के एक बोर्ड का गठन किया था, जिसने धीरज वधावन की मेडिकल स्थिति का आकलन किया। बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में बताया

कि आरोपी को किसी भी तत्काल मेडिकल सहायता या इलाज की आवश्यकता नहीं है। इस रिपोर्ट के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए और बचाव पक्ष के वकीलों की जोरदार दलीलों के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के 9 सितंबर, 2024 के आदेश को निरस्त कर दिया। इस मामले में सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने बहस की।

वित्त वर्ष 2023 और 2024 में क्रिप्टो ट्रांजैक्शन के जरिए 630 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला : केंद्र

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने संसद को सूचित किया कि केवल दो वित्त वर्षों में वर्चुअल डिजिटल एसेट (वीडीए) ट्रांजैक्शन में लगभग 630 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता लगाया गया। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीबीएच के तहत वीडीए के ट्रांसफर से होने वाली आय पर कर वित्त वर्ष 2022-23 से लागू किया गया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए करदाताओं द्वारा दी गई कुल कर राशि 705 करोड़ रुपए के बराबर थी। इसके अलावा, तलाशी और जब्ती अभियान और सर्वेक्षण अभियान के दौरान, वीडीए ट्रांजैक्शन में लगभग 630 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने क्रिप्टोकरेंसी और वीडीए में निवेश से जुड़े कर चोरी के मामलों का पिछले कुछ समय में कई बार पता लगाया है और ऐसे मामलों में आयकर विभाग द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है। राज्य मंत्री के अनुसार, वीडीए के प्रकटीकरण और कर भुगतान के संबंध में करदाताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए, सीबीडीटी ने हाल ही में करदाताओं के लिए एनयूडीजीई (गाइड और इनेबल करने के लिए डेटा का गैर-घुसपैठिया उपयोग) अभियान शुरू किया है, जिसके तहत उन चुनिंदा करदाताओं को 44,057 ईमेल और संदेश भेजे गए हैं जिन्होंने वीडीए में निवेश और व्यापार किया था, लेकिन अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) की अनुसूची वीडीए में ट्रांजैक्शन की सूचना नहीं दी थी। सीबीडीटी ने क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन से होने वाली आय की सटीक रिपोर्टिंग और कराधान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहल की हैं। इनमें नॉन-फाइलर मॉनिटरिंग सिस्टम (एनएमएस), प्रोजेक्ट इनसाइट और आयकर विभाग के आंतरिक डेटाबेस जैसे डेटा एनालिटिक्स टूल्स का उपयोग शामिल है, ताकि वीडीए ट्रांजैक्शन पर उपलब्ध जानकारी को करदाताओं के आयकर रिटर्न (आईटीआर) में किए गए खुलासे से जोड़ा जा सके।

राज्य मंत्री ने कहा कि वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (वीएएसपी) द्वारा दाखिल टीडीएस रिटर्न और करदाताओं द्वारा दाखिल आईटीआर का भी विश्लेषण किया जाता है ताकि रिपोर्ट किए गए वीडीए ट्रांजैक्शन में विसंगतियों की पहचान की जा सके और उचित कार्रवाई की जा सके।

स्टॉक मार्केट में टाक्यों नेटवर्क्स की सपाट शुरुआत, लिस्टिंग के बाद लगा लोअर सर्किट

एजेंसी

नई दिल्ली। आईटी सॉल्यूशंस मुहैया कराने वाली कंपनी टाक्यों नेटवर्क्स के शेयरों की आज स्टॉक मार्केट में सपाट स्तर पर मामूली बढ़त के साथ एंट्री हुई। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 54 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 3.43 प्रतिशत प्रीमियम के साथ इसकी लिस्टिंग 55.85 रुपये के स्तर पर हुई। लिस्टिंग के बाद बिकवाली शुरू हो जाने के कारण थोड़ी देर में ही ये शेयर गिर 53.06 रुपये लोअर सर्किट लेवल पर आ गया। इस तरह पहले दिन के कारोबार में ही कंपनी के आईपीओ निवेशकों को 1.74 प्रतिशत का नुकसान हो गया हैटाक्यों नेटवर्क्स का 20.48 करोड़ रुपये का आईपीओ 30 जुलाई से एक अगस्त के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 21.77 गुना सब्सक्राइब हो सका था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 13.29 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इसी तरह नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 37 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 19.99 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 37.92 लाख नए शेयर जारी किए गए हैं। आईपीओ के जरिये जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपने पुराने कर्ज को चुकाने, वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी। कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो प्रॉस्पेक्टस में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी को 2.81 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 5.22 करोड़ रुपये और 2024-25 में उछल कर 6.96 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी का राजस्व 27 प्रतिशत वार्षिक से अधिक की चक्रवृद्धि दर (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) से बढ़ कर 103.48 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

वैश्विक साइबर धोखाधड़ी मामले में दिल्ली-एनसीआर में 11 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को वैश्विक साइबर धोखाधड़ी के एक मामले में मनीलॉड्रिंग जांच के तहत दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और देहरादून स्थित 11 ठिकानों पर छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने

बताया कि (ईडी) ने एक वैश्विक साइबर धोखाधड़ी गिरोह से जुड़े मनीलॉड्रिंग जांच के तहत राजधानी दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और देहरादून स्थित 11 परिसरों में सर्च ऑपरेशन चला रहा है। सीबीआई और दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर के आधार पर केंद्रीय जांच एजेंसी धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत जांच कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि इस गिरोह ने भारतीय और विदेशी नागरिकों से करोड़ों रुपये की ठगी की है। जांच से पता चला कि आरोपितों ने कई क्रिप्टो-वॉलेट में बिटकॉइन के रूप में 260 करोड़ रुपये जमा किए थे, जिन्हें बाद में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में कई हवाला ऑपरेटरों/व्यक्तियों के माध्यम से यूएसडीटी में परिवर्तित करके नकदी में बदल दिया गया।

सरकार ने पहल और आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से एलपीजी सब्सिडी ट्रांसफर को किया मजबूत : हरदीप पुरी

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी वितरण और सब्सिडी हस्तांतरण को कुशल, पारदर्शी और समावेशी बनाने के लिए निरंतर कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि पहल (डीबीटीएल) स्कीम, आधार-आधारित सत्यापन, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और अयोग्य या नकली कनेक्शनों को हटाने जैसी पहलों से लक्षित सब्सिडी ट्रांसफर सिस्टम काफी मजबूत हुआ। केंद्रीय मंत्री पुरी ने बताया कि देश भर के सभी एलपीजी वितरकों में आईवीआरएस/एसएमएस रिफिल बुकिंग सिस्टम लागू किया गया है। इस सिस्टम के तहत, उपभोक्ताओं को रिफिल बुकिंग, कैश मेमो जनरेशन और रिफिल डिलीवरी जैसे प्रमुख चरणों पर एसएमएस के जरिए सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जिससे वे अपने लेन-देन को ट्रैक कर सकते हैं और गलत या न मिलने की स्थिति में रिपोर्ट कर सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) शुरू किया है, जो कैश मेमो जनरेशन के समय उपभोक्ता को एसएमएस के माध्यम से भेजा जाता है और डिलीवरी के समय डिलीवरी कर्मियों के साथ साझा करना आवश्यक होता है, जिससे प्रमाणीकरण सुनिश्चित होता है। अनुपालन सुनिश्चित करने को लेकर केंद्रीय मंत्री ने बताया कि तेल विपणन कंपनियों के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा एलपीजी वितरकों का नियमित निरीक्षण किया जाता है। इसके अलावा, क्षेत्रीय, जोनल, डिविजनल कार्यालयों और प्रादेशिक

कार्यालयों के अधिकारी, एंटी-एडल्टरेशन सेल, क्वालिटी रिएश्योरेंस सेल और विजिलेंस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर वितरकों के गोदामों, शोरूमों, वितरण स्थलों की जांच करते हैं, ताकि एलपीजी का दुरुपयोग रोका जा सके। केंद्रीय मंत्री पुरी ने बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण अभियान को लेकर कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाओं के लिए आधार-आधारित प्रमाणीकरण, लाभार्थियों की सटीक, वास्तविक समय पर और लागत प्रभावी पहचान, प्रमाणीकरण और दोहराव को कम करने में सक्षम बनाता है।

1 जुलाई तक मौजूदा पीएमयूवाई लाभार्थियों में से 67 प्रतिशत का बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा हो चुका है। इसके अलावा, सभी नए पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को कनेक्शन जारी होने से पहले बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से गुजरना होगा। डुप्लीकेशन हटाने की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, 8.49 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) कनेक्शन समाप्त कर दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि जनवरी 2025 में, उन पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को हटाने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई थी, जिन्होंने कनेक्शन लगने के बाद कोई रिफिल नहीं लिया था।

इस एसओपी के तहत, लगभग 12,000 निष्क्रिय पीएमयूवाई कनेक्शन समाप्त कर दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि 2024-25 के दौरान, लगभग 194 करोड़ एलपीजी रिफिल उपभोक्ताओं को वितरित किए गए और इनमें से केवल 0.08 प्रतिशत के लिए शिकायतें प्राप्त हुईं, जो कि ज्यादातर सब्सिडी हस्तांतरण या वितरण में देरी से संबंधित थी।

ट्रंप ने कहा-अमेरिका के लिए भारत अच्छा व्यापारिक साझेदार नहीं

एजेंसी

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप ने कहा कि भारत का शुल्क (टैरिफ) बहुत ज्यादा है। इसलिए अमेरिका उसके साथ कम व्यापार करता है। उन्होंने कहा कि इसलिए अमेरिका के लिए भारत अच्छा व्यापारिक साझेदार नहीं है। द व्हाइट हाउस ने अपने समाचार प्रभाग में सीएनबीसी को दिए राष्ट्रपति ट्रंप के साक्षात्कार के मुख्य अंश पांच अगस्त को प्रसारित किए हैं। इनमें यह बात कही गई है। ट्रंप ने कहा कि भारत हमारे साथ बड़ा व्यापार करता है। अमेरिका उस अनुपात में भारत के साथ काफी कम व्यापार करता है। उन्होंने कहा, इसलिए मैं 25 फीसद टैरिफ पर सहमत हुआ हूं। मुझे लगता है कि मैं अगले 24 घंटों में इसे काफी बढ़ा दूंगा। भारत रूस से तेल खरीद रहा है। यही नहीं भारत युद्धक विमानों को ईंधन दे रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सीएनबीसी के स्क्रॉक बॉक्स में अपने दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाईं। राष्ट्रपति ट्रम्प ने चीन के साथ संबंधों पर कहा, यदि हम कोई समझौता कर लेते हैं, तो सबसे अधिक संभावना है कि मैं वर्ष के अंत से पहले चीन के साथ बैठक करूंगा। वैसे भी हम समझौते के बहुत करीब पहुंच रहे हैं।

टैरिफ नीति पर ट्रंप को निक्की हेली की सलाह- भारत जैसे मजबूत सहयोगी से रिश्ते न बिगाड़ें

वॉशिंगटन। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत से रिश्ते न बिगाड़ने की सलाह दी है।पूर्व राजदूत हेली ने कहा है कि भारतीय सामानों पर भारी टैरिफ से भारत-अमेरिकी संबंधों में खटास आ सकती है।इससे पहले ट्रंप ने एकबार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह अगले 24 घंटों में भारत पर टैरिफ और बढ़ाएंगे।हालांकि ट्रंप ने भारत की तरफ से दिए गए उस तथ्य की जानकारी न होने की बात कही, जिसमें भारत ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ खुद रूस के साथ व्यापार जारी रखे हुए हैं। टैरिफ को लेकर भारत अमेरिका तनाव पर भारतीय मूल की पूर्व अमेरिकी राजदूत निक्की हेली ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अहम सलाह देते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही मित्रता में खटास आने का जोखिम है उन्होंने ट्रंप पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए एक्स पोस्ट में लिखा- भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए लेकिन रूस व ईरान के सबसे बड़े तेल खरीदार चीन को 90 दिनों की टैरिफ छूट मिल गई।भारत जैसे मजबूत सहयोगी से रिश्ते बिगाड़ कर चीन को छूट न दें।

इजराइल की गाजा में पूर्ण सैन्य नियंत्रण की योजना पर विचार, सैन्य और जनमत से टकराव

तेल अवीव। इजराइल सरकार गाजा पट्टी के उस 25 प्रतिशत क्षेत्र में भी सेना तैनात करने पर विचार कर रही है, जो अभी उसके नियंत्रण में नहीं है। हालांकि इस संभावित कदम को लेकर सैन्य नेतृत्व और देश की अधिकांश जनता में चिंता जताई जा रही है कि इससे हमास के कब्जे में बचे बंधकों की रिहाई की संभावनाएं कमजोर हो सकती हैं। एक वरिष्ठ इजराइली अधिकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस निर्णय को अंतिम रूप देने से पहले अपनी सुरक्षा कैबिनेट की बैठक इसी सप्ताह बुला सकते हैं। नेतन्याहू ने तीन घंटे लंबी सुरक्षा बैठक की, जिसमें आईडीएफ (इजराइल डिफेंस फोर्सेस) के चीफ ऑफ स्टाफ एयाल जामिर ने सैन्य विकल्पों की प्रस्तुति दी। आईडीएफ ने साफ किया है कि सुरक्षा कैबिनेट द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को लागू करने के लिए वह तैयार है। गाजा में जारी लगभग दो वर्ष लंबे युद्ध को लेकर इजराइल पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि खाद्य आपूर्ति पर इजराइली प्रतिबंध और युद्ध से हुई तबाही के कारण गज़ा में भुखमरी का खतरा बढ़ रहा है। जुलाई के अंत में इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र और एनजीओ के माध्यम से मानवीय सहायता के वितरण को आसान बनाने का वादा किया था। सरकार ने खाद्य और स्वच्छता सामग्री की वाणिज्यिक पहुंच में कुछ और ढील देने की घोषणा की, लेकिन यह कड़ी सुरक्षा जांच के अधीन रहेगी।

मोल्डोवा में चुनावी धोखाधड़ी पर रूस समर्थक क्षेत्रीय नेता को 7 साल की सजा

किशिनाव। मोल्डोवा की एक अदालत ने दक्षिणी क्षेत्र गागाउजिया की नेता और रूस समर्थक राजनेता येवगेनिया गुटुल को चुनावी धोखाधड़ी के मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब देश में आगामी 28 सितंबर को महत्वपूर्ण संसदीय चुनाव होने जा रहे हैं। गुटुल पर आरोप था कि उन्होंने 2019 से 2022 के बीच रूस से अवैध फंडिंग के जरिए मोल्डोवा में एक राजनीतिक दल को आर्थिक सहायता पहुंचाई। यह पार्टी ईलान शोर द्वारा स्थापित की गई थी, जो स्वयं मोल्डोवा में धोखाधड़ी के दोषी करार दिए जा चुके हैं और फिलहाल रूस में निर्वासित जीवन जी रहे हैं। गुटुल, जो शोर की अब प्रतिबंधित पार्टी की पूर्व सचिव भी रही हैं, 2023 में गागाउजिया की गवर्नर चुनी गईं। उस चुनाव पर भी वोट खरीद के आरोप लगे थे। यूरोपीय संघ ने उन्हें मोल्डोवा में ÷जनीतिक अस्थिरता और क्षेत्रीय अलगाववाद को बढ़ावा देने के आरोप में प्रतिबंधित कर रखा है। गुटुल ने अदालत के इस फैसले को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताते हुए अपील करने की घोषणा की है।

बांग्लादेश में यूनुस सरकार की कार्रवाई तेज, अवामी लीग के 1,593 नेता-कार्यकर्ता गिरफ्तार

एजेंसी

ढाका। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार द्वारा अवामी लीग के खिलाफ जारी सख्त कार्रवाई के तहत बांग्लादेश पुलिस ने अब तक देशभर से 1,593 अवामी लीग नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में दी गई। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (डीएमपी) ने भी राजधानी के विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर 11 अवामी लीग कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। डीएमपी के डिप्टी कमिश्नर मुहम्मद तालेबुर रहमान ने इसकी पुष्टि की है। गिरफ्तार किए गए लोगों में अवामी लीग समर्थक और प्रसिद्ध ब्लॉगर कमाल पासा चौधरी भी शामिल हैं। बांग्लादेश के प्रमुख बांग्ला अखबार ने इस बात की जानकारी दी है। कमाल पासा चौधरी की गिरफ्तारी की आलोचना करते हुए, अवामी लीग के नेता और पूर्व राज्य सूचना एवं प्रसारण मंत्री मोहम्मद आराफात

ने इसे अन्यायपूर्ण करार दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, मुक्ति संग्राम समर्थक कमाल पासा चौधरी को अन्यायपूर्ण रूप से गिरफ्तार किया गया है। यह यूनुस के तानाशाही शासन में प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष आवाजों को दबाने की एक और कोशिश है। आराफात के अनुसार, कमाल पासा चौधरी को ढाका के ललमाटिया इलाके में एक कार्यालय से डिटेक्टिव ब्रांच (डीबी) ने गिरफ्तार किया और उन पर कोई स्पष्ट आरोप नहीं लगाया गया।

अवामी लीग की मीडिया सेल का कहना है कि देश में फर्जी मामलों, भीड़ हिंसा और राजनीतिक बदले की भावना के मामलों में तेज़ी से इज़ाफा हो रहा है। पार्टी ने दावा किया कि न्यायिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और अदालतें अब न्याय का मंच नहीं, बल्कि राजनीतिक नाटक का मंच बन चुकी हैं। पार्टी का यह भी आरोप है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनके समर्थकों और कार्यकाल के दौरान कार्यरत अधिकारियों के खिलाफ झूठे और मनगढ़ंत आरोपों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इस बीच, अंतरिम सरकार पर कट्टरपंथी और उग्रपंथी इस्लामी संगठनों को शरण देने का भी आरोप लगा है, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना तेज हो गई है।

बीएलए ने बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली, हमले में पाकिस्तान की सेना के मेजर समेत तीन सैन्यकर्मियों को मार गिराने का दावा

एजेंसी

इस्लामाबाद। बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने बलूचिस्तान के नुश्की जिले में हुए बम विस्फोट की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया कि उसके हमले पाकिस्तान की सेना के एक मेजर समेत तीन सैन्यकर्मी मारे गए और तीन अन्य घायल हो गए। बीएलए ने दावा किया कि उसकी खुफिया शाखा जिराब की पुख्ता सूचना पर मेजर के काफिले को निशाना बनाया गया।

द बलूचिस्तान पोस्ट ने बीएलए प्रवक्ता जीयंद बलूच के हवाले से यह खबर प्रसारित की है। यह हमला रात करीब 8:00 बजे नुश्की जिले के गरगिना इलाके में एक सड़क किनारे लगे इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) से एक बुलेटप्रूफ सैन्य वाहन को निशाना बनाकर किया गया। मृतकों की पहचान मेजर रिजवान, नायब सूबेदार अमीन और लांस नायक यूनिस के रूप में होने का दावा किया गया है। पाकिस्तान की सेना ने अभी

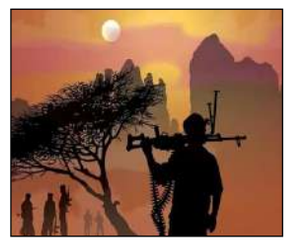

तक इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की है। बीएलए प्रवक्ता जीयंद बलूच ने दावा किया कि लड़ाकों ने जिराब की सूचना के आधार पर मेजर रिजवान के काफिले को निशाना बनाया। इस हमले की पूरी जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी लेती है।

बाइडेन के नेतृत्व में रूस-अमेरिका संबंधों में अभूतपूर्व गिरावट आई थी : क्रेमलिन

एजेंसी

मास्को । मास्को ने बुधवार को कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप के बीच अब तक कोई बैठक न होने पर उसे कोई हैरानी नहीं है।, क्योंकि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान रूस-अमेरिका संबंधों में अभूतपूर्व गिरावट आई थी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने इस बात पर जोर दिया कि रूस के आधुनिक इतिहास में पहली बार है जब नए अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के छह महीने से ज्यादा समय बाद भी अमेरिका-रूस शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं हुआ है। पहले, रूस-अमेरिका शिखर सम्मेलन का इंतजार आमतौर पर एक से पांच महीने तक होता था। लेकिन इस बार, ट्रंप के राष्ट्रपति पद संभालने के छह महीने और 16 दिन बीत चुके हैं। हालांकि, रूसी सरकारी समाचार एजेंसी टीएएसएस की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति और पुतिन के बीच कोई व्यक्तिगत

मुलाकात नहीं हुई है। पेसकोव ने कहा, किसी अनोखी स्थिति के बारे में बात करना असंभव है। आखिरकार, पिछले (अमेरिकी) प्रशासन के तहत, हमारे द्विपक्षीय संबंधों में अभूतपूर्व गिरावट आई थी। उन्होंने कहा कि बाइडेन के नेतृत्व में, मास्को और वाशिंगटन के बीच अभूतपूर्व संख्या में परेशान करने वाली चीजें इकट्ठी हो गईं। अमेरिकी प्रतिबंधों की समयसीमा को लेकर बढ़ते तनाव के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ बुधवार को रूसी नेताओं के साथ बैठक करने के लिए मास्को में होंगे। विटकॉफ की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब रूस और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा है।ट्रंप ने यह भी पुष्टि की कि अगर यूक्रेन संकट के समाधान पर कोई समझौता नहीं हुआ, तो 9 अगस्त तक रूस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

बीवाईसी ने बलूचिस्तान में संघीय सरकार के चेहल्लुम यात्रा मार्ग पर प्रतिबंध लगाने के फैसले की आलोचना की

एजेंसी

क्वेटा। बलूचिस्तान के नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की वकालत करने वाले समूह बलूच यकजेहती समिति (बीवाईसी) ने संघीय सरकार के हाल ही में बलूचिस्तान से होकर चेहल्लुम के लिए इराक जाने वाले शिया तीर्थयात्रियों के काफिले पर प्रतिबंध लगाने के फैसले की निंदा की है। समूह ने इस कदम को संवैधानिक और मौलिक अधिकारों का उल्लंघनऔर इसे तथाकथित सुरक्षा के नाम पर किया गया धार्मिक भेदभाव बताया है। बीवाईसी की यह प्रतिक्रिया पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणी के बाद आई है। आसिफ ने इस्लामाबाद में कहा था कि सरकार ने तीर्थयात्रियों के काफिले को निशाना बनाकर आतंकवादी हमलों के खतरे के कारण क्वेटा से 800 किलोमीटर के भूमि मार्ग पर यात्रा प्रतिबंधित कर दी है। द बलूचिस्तान पोस्ट की खबर के अनुसार, बीवाईसी ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है।

तथाकथित सुरक्षा के नाम पर लगाया गया कोई भी प्रतिबंध अस्वीकार्य है। समूह ने आरोप लगाया कि राज्य ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने मूल कर्तव्य को पूरा करने के बजाय यह प्रतिबंध लगाया है। बीवाईसी ने कहा, राज्य की जिम्मेदारी धार्मिक अनुष्ठान करने वाले नागरिकों के लिए सुरक्षित मार्ग प्रदान करना है, न कि आस्था के आधार पर उन्हें बाधित करना। बीवाईसी ने बयान में कहा कि कि शिया तीर्थयात्रियों ने प्रतिबंध के विरोध में कराची से रिमदान सीमा तक लंबे मार्च की घोषणा की है। समूह ने इस मार्च को संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार बताया और विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वालों के साथ अपना पूर्ण समर्थन और एकजुटता व्यक्त की।बीवाईसी ने कहा, हम मांग करते हैं कि शिया तीर्थयात्रियों के कारवां पर प्रतिबंध तुरंत हटाया जाए और बलूचिस्तान से ईरान और इराक जाने वालों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए। बयान में अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि वे बल प्रयोग या दबाव के जरिए मार्च में बाधा डालने का प्रयास न करें। गौरतलब है कि पाकिस्तान के संघीय गृहमंत्री ने भी हाल ही में घोषणा की थी कि शिया तीर्थयात्रियों को बलूचिस्तान के रास्ते इराक जाने से रोका जाएगा।

टीटीपी का खैबर कबायली जिले की अशांत तिराह घाटी के आदिवासियों से समझौता

एजेंसी

इस्लामाबाद। प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने इस बात पर सहमति जताई कि वह सुरक्षा बलों के खिलाफ अपने सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल नहीं करेगा। टीटीपी नेताओं ने यह भी वादा किया कि अब से खैबर कबायली जिले की अशांत तिराह घाटी में जकात और उशर के नाम पर किसी से जबरन वसूली नहीं की जाएगी। डान अखबार की खबर के अनुसार टीटीपी के लेटरहेड पर पश्तो भाषा में लिखे और उसकी सर्वोच्च परिषद (रहबारी शूरा) की मुहर लगे इस समझौते को बार कंबरखेल के एक बुजुर्ग ने स्थानीय आदिवासियों के सामने पढ़ा। यह समझौता आम आदिवासियों के खिलाफ शत्रुता समाप्त करने और शांति बहाल करने के लिए तिराह से वापसी की उनकी मांग के जवाब में किया गया है। खैबर के तिराह में बार

कंबरखेल जनजाति के जिरगा के दौरान यह समझौता हुआ।

इस दौरान प्रतिबंधित टीटीपी नेताओं ने सुरक्षा बलों के खिलाफ अपना सशस्त्र प्रतिरोध जारी रखने और उन लोगों को सजा देने की कसम खाई, जिन्होंने सुरक्षा बलों का समर्थन किया या उनके खिलाफ जासूसी करने के दोषी पाए गए। समझौते में कहा गया है कि हमारा एकमात्र उद्देश्य इस्लाम विरोधी ताकतों और उनके सहयोगियों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष (जिहाद) है।हम स्थानीय लोगों के आंतरिक और निजी मामलों में अपनी भागीदारी को अनुचित मानते हैं और इसलिए हमने अपने स्वयंसेवकों को ऐसा करने से सख्त मना किया है। समझौते में स्पष्ट किया गया है कि टीटीपी सदस्य लोगों के घरों में शरण नहीं लेंगे या सुरक्षा बलों के खिलाफ बंकर के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वे ऐसी किसी भी निजी इमारत में सुरक्षा बलों के रुकने का विरोध करेंगे। टीटीपी नेताओं ने यह भी सहमति व्यक्त की कि लड़ाके किसी का अपहरण या उत्पीड़न नहीं करेंगे। तिराह के बार कंबरखेल में बातचीत का पहला दौर 28 जुलाई को हुआ था। इस दौरान टीटीपी के स्थानीय कमांडरों ने अफगानिस्तान में अपने नेतृत्व को जिरगा की मांगों से अवगत कराने के लिए पांच अगस्त तक का समय मांगा था।

अमेरिकी न्याय विभाग को जेफरी एपस्टीन से जुड़ी फाइलें सौंपने के लिए समन

एजेंसी

वाशिंगटन। हाउस ओवरसाइट कमेटी अध्यक्ष जेम्स कॉमर ने अमेरिकी न्याय विभाग को समन जारी किया। विभाग से कहा गया है कि वह नाबालिग लड़कियों की तस्करी के आरोपित जेफरी एपस्टीन से जुड़ी पूरी फाइलें सौंप दे। कॉमर ने दूसरा समन पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और पूर्व विदेशमंत्री हिलेरी क्लिंटन की गवाही के लिए जारी किया गया है। कॉमर ने कहा कि वह चाहते हैं कि न्याय विभाग 19 अगस्त तक या उससे पहले पूरी फाइलें सौंप दे। एबीसी न्यूज के अनुसार, कॉमर ने यह जानकारी देते हुए कहा कि विभाग एपस्टीन और मैक्सवेल के मामलों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी को सार्वजनिक करने का प्रयास कर रहा है। यह आवश्यक है कि कांग्रेस संघीय सरकार यौन तस्करी कानूनों के प्रवर्तन और विशेष रूप से एपस्टीन और मैक्सवेल की जांच और अभियोजन के संचालन की निगरानी करे। कॉमर ने न्याय विभाग की आला अधिकारी अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को भेजे समन में यह उल्लेख किया है। क्लिंटन दंपत्ति के अलावा, रिपब्लिकन नेतृत्व वाले पैनल ने जेम्स कॉमी, लोरेटा लिंच, एरिक होल्डर, मेरिक गारलैंड, रॉबर्ट म्यूलर, विलियम बार, जेफ सेशंस और अल्बर्टो गोंजालेस के बयान दर्ज कराने के लिए भी समन जारी किए है। कमेटी के रिपब्लिकन सदस्यों ने कहा कि वे इन लोगों से एपस्टीन संबंधी फाइलों के संबंध में जानकारी मांग रहे हैं। कुछ रिपब्लिकन वर्षों से एपस्टीन मामले से जुड़ी साजिशों और षड्यंत्रों को हवा दे रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार इस पर अपनी राय दे चुके हैं। कुछ ने सवाल उठाया है कि इन दोनों की कथित ग्राहक सूची में और कौन हो सकता है। न्याय विभाग और एफबीआई ने पिछले महीने एक संक्षिप्त बयान में कहा था कि समीक्षा में पाया गया कि ऐसी कोई सूची मौजूद नहीं है।

कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग, सैकड़ों इमारतों पर मंडरा रहा खतरा

एजेंसी

लॉस एंजिल्स । मध्य कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग ने अब तक 82,000 एकड़ (लगभग 332 वर्ग किलोमीटर) से ज्यादा इलाके को अपनी चपेट में लिया है। यह आग पिछले पांच दिनों से भयानक रूप ले चुकी है और सैकड़ों इमारतों को खतरा बना हुआ है। अमेरिकी वन सेवा और कैलिफोर्निया के वानिकी व अग्नि सुरक्षा विभाग के अनुसार, 'गिफोर्ड फायर' नाम की यह जंगल की आग शुक्रवार दोपहर उस समय भड़क उठी, जब कैलिफोर्निया हाईवे के पास चार अलग-अलग जगहों पर आग लग गई और उन्होंने मिलकर एक विकराल आग का रूप धारण कर लिया। यह आग अब सैन लुइस ओबिस्पो और सांता बारबरा काउंटी में सांता लूसिया रोड के पास फैल रही है एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि आग की

चपेट में आने से 870 से ज्यादा इमारतें खतरे में हैं। मंगलवार सुबह तक इस आग पर सिर्फ 7 प्रतिशत ही काबू पाया जा सका है। आग की वजह से सांता बारबरा और सैन लुइस ओबिस्पो के लोगों को अपने घर खाली करने का आदेश दिया गया है। अमेरिकी वन सेवा के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए चेतावनी दी कि आग के अनियमित फैलाव के कारण लोगों को अपने इलाके की बदलती स्थिति पर ध्यान रखना चाहिए। अधिकारियों ने बताया कि इलाके में गर्मी और सूखा मौसम बुधवार से सप्ताह के अंत तक बना रह सकता है, इसलिए आग पर काबू पाने के लिए दमकलकर्मी उत्तर और दक्षिण दिशा में लगातार प्रयास करते रहेंगे। इंसीवेब (अमेरिकी एजेंसी की आपात स्थिति प्रबंधन प्रणाली) के अनुसार, आग बुझाने के लिए 1,900 से ज्यादा दमकलकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 40 हैंड क्रू, 115 फायर इंजन, 23 बुलडोज़र और 30 पानी के टैंकर भी लगाए गए हैं। इन्हें हवाई टैंकरों और हेलीकॉप्टरों की मदद भी मिल रही है। सांता बारबरा काउंटी अग्निशमन विभाग के प्रवक्ता कैप्टन स्कॉट सेफचुक ने बताया कि आग ऊंची और खड़ी ढलानों पर फैल रही है और इससे बहुत ज्यादा धुआं उठ रहा है। सेफचुक ने कहा, आग का ज्यादातर हिस्सा ऐसे दुर्गम इलाकों में है, जहां बुलडोज़र भी नहीं पहुंच सकते। उन्होंने बताया कि आग बुझाने के लिए अब विमानों की भी मदद ली जा रही है। राष्ट्रीय मौसम सेवा के लॉस एंजिल्स कार्यालय ने बताया कि यह धुआं दक्षिण-पश्चिम कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों को प्रभावित कर सकता है। जंगल की आग से उठने वाला धुआं स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है और इसके दक्षिण और पूर्व की ओर फैलने की आशंका है।

अमेरिकी विदेश विभाग ने ट्रंप की टैरिफ धमकी पर भारत की प्रतिक्रिया पर टिप्पणी से किया इनकार

एजेंसी

न्यूयॉर्क । अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने भारत की उन प्रतिक्रियाओं पर टिप्पणी करने से मना कर दिया, जिनमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। एक पत्रकार द्वारा विदेश मंत्री एस. जयशंकर की टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने कहा, ÷मैं किसी अन्य देश की इस टिप्पणी पर कोई राय नहीं दूंगी कि वे क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं तो मुश्किल से यहां भी ऐसा कर पाती हूं। उन्होंने थोड़ी हैरानी जताते हुए कहा, मैं तो मुश्किल से यहां भी ऐसा कर पाती हूं। लेकिन उन्होंने भारत द्वारा तेल खरीद की आलोचना करते हुए कहा कि ट्रंप ही ÷मार्गदर्शक हैं, और रूस जो कर रहा है और वे देश जो यूक्रेन के खिलाफ इस युद्ध में मदद कर रहे हैं, तो यह राष्ट्रपति ट्रंप पर निर्भर करेगा कि वे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। ट्रंप के बयान के बाद आयोजित नियमित ब्रीफिंग में ब्रूस ने पत्रकारों से बात करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि वह रूस से तेल खरीदने और उससे बने उत्पादों को फिर से बेचने पर भारत पर 24 घंटे के भीतर 25 प्रतिशत से अधिक का भारी शुल्क लगाएंगे।उन्होंने आरोप लगाया, वे रूसी तेल खरीद रहे हैं और रूसी युद्ध मशीन को ईंधन दे रहे हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने सोमवार को टैरिफ के खतरे की अप्रत्यक्ष आलोचना करते हुए कहा हम जटिल और अनिश्चित समय में जी रहे हैं। हमारी सामूहिक इच्छा एक निष्पक्ष और प्रतिनिधित्वपूर्ण वैश्विक व्यवस्था देखना है, न कि कुछ लोगों के प्रभुत्व वाली। हालांकि जयशंकर ने अपने बयान में ट्रंप का जिक्र नहीं किया। विदेश मंत्रालय ने कहा, किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह, भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। उन्होंने भारत को अलग-थलग करने के अंतर्निहित दोहरे मानदंडों की भी आलोचना की और बताया कि यूरोपीय संघ का रूस के साथ व्यापार 67.5 अरब डॉलर का है, और वाशिंगटन यूरेनियम, पैलेडियम, उर्वरक और अन्य रसायन भी खरीद रहा है।

ट्रंप की चेतावनी- यूरोपीय संघ ने निवेश का वादा नहीं निभाया तो लगेगा 35 प्रतिशत टैरिफ

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यूरोपीय संघ (ईयू) को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि यदि यूरोपीय संघ अमेरिका के साथ हुए समझौते के तहत 600 अरब डॉलर का निवेश पूरा नहीं करता है, तो अमेरिका उसकी वस्तुओं पर 35 प्रतिशत टैरिफ (आयात शुल्क) लगाएगा। एक जनसभा में ट्रंप ने कहा, उन्होंने (ईयू) अपने टैरिफ घटाए। उन्होंने हमें 600 अरब डॉलर दिए, जिसके बदले मैंने उनके टैरिफ 30 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिए। कुछ देशों ने पूछा कि उन्हें कम टैरिफ क्यों मिल रहा है, तो मैंने कहा, क्योंकि उन्होंने मुझे 600 अरब डॉलर दिए।ट्रंप ने दावा किया कि यह रकम उपहार की तरह है, न कि कोई ऋण। यह पैसा हम किसी भी क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं। ईयू ने वर्षों से हमारा शोषण किया है, अब समय है कि वे इसकी भरपाई करें। उन्होंने स्विट्ज़रलैंड की प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वह उनके तर्क सुनने को तैयार नहीं थीं। ट्रंप ने फार्मास्युटिकल (दवा) उद्योग को लेकर भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा, वे फार्मा उत्पादों से भारी मुनाफा कमाते हैं, और उन्हें चीन और आयरलैंड जैसे देशों में बनाते हैं। मैं अगले एक-दो हफ्तों में इन पर अलग से टैरिफ की घोषणा करूंगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह टैरिफसामान्य 15 प्रतिशत टैरिफ से अलग होंगे और इन्हें वहविशेष श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं।

ईरान ने हजारों अफगान शरणार्थियों को वापस भेजा, अफगानिस्तान रोजगार बाजार पर दबाव बढ़ा

एजेंसी

काबुल । ईरान ने लंबे समय से कृषि, निर्माण और कुशल व्यवसायों जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हजारों अफगान शरणार्थियों को वापस भेज दिया है। बड़ी संख्या में अफगानों की अचानक वापसी से अफगानिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ रहा है। रोजगार के अवसरों और आवश्यक सहायता सेवाओं की भारी कमी देखी जा रही है। ईरान के कृषि क्षेत्र में चार साल तक काम करने वाले अफगान प्रवासियों में से एक, अब्दुल रहीम ने कहा कि अगर उनके देश में रोजगार के अवसर उपलब्ध हों, तो वह अपने कौशल से अपने छह सदस्यों वाले परिवार का भरण-पोषण कर सकते हैं। अफगान मीडिया आउटलेट टोलो न्यूज ने रहीम के हवाले से कहा, हम अब अपने देश लौट आए हैं। हम ईरान में कृषि संबंधी कार्य करते थे। अगर यहां कृषि क्षेत्र में अवसर मिलता है, तो मुझे खुशी होगी।

एक अन्य अफगान प्रवासी ने कहा, अगर ईरान में हमने जो काम किया, वह हमारे देश में उपलब्ध होता, तो हम कभी ईरान नहीं जाते। ईरानी सरकार और वहां के लोगों ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया। हमने वहां घर किराए पर लिए, और वे हमें हमारी मजदूरी नहीं देते।÷ हाल ही में,

अफगान शरणार्थी मामलों के आयोग के प्रवक्ता अहमदुल्लाह वसीक ने अफगान प्रवासियों के साथ दुर्व्यवहार के लिए ईरानी सरकार की निंदा की और उनसे निर्वासन प्रक्रिया के लिए अफगान सरकार के साथ समन्वय करने का आग्रह किया।

उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संगठनों से शरणार्थी मामलों के आयोग के साथ समन्वय करके लौटने वालों के लिए मानवीय सहायता बढ़ाने का आह्वान किया। टोलो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले ईरान से निर्वासित लोगों में से एक, फातिमा, जो तीन साल से अपने परिवार के साथ ईरान में रह रही थी, ने ईरानी अधिकारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहारों का जिक्र किया था।

उन्होंने कहा, हमें शिविर से लाया गया था, और उन्होंने हमें कुछ भी न लाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि वे हमारी मदद करेंगे। लेकिन रास्ते में, किसी ने हमें कुछ नहीं दिया; मेरे बच्चे भूखे रहे। यात्रा के दौरान उन्होंने हमें परेशान किया और हमारे पैसे व फोन छीन लिए।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 की शुरुआत से 1 अगस्त तक, 21 लाख से ज्यादा अफगानों को ईरान और पाकिस्तान से निर्वासित करके उनके देश वापस भेजा गया है। रिपोर्ट के अनुसार, 1 अप्रैल से 30 जुलाई तक, ईरान से 14 लाख और पाकिस्तान से 3,03,300 अफगान अफगानिस्तान लौटे हैं। 2025 तक ईरान और पाकिस्तान से 21 लाख से ज्यादा अफगान वापस आ चुके हैं। अफगानिस्तान की स्थिति बेहद कमजोर है। उसे इस वर्ष के लिए आवश्यक 478 मिलियन डॉलर का केवल 24 प्रतिशत ही मिल पाया है।

ईरान और पाकिस्तान से निर्वासित कई अफगान प्रवासियों ने आश्रय, बेरोजगारी और बुनियादी सेवाओं की कमी के कारण अपने देश में कठिन जीवन स्थितियों के बारे में चिंता जताई है।

'निवेश मित्र 3.0' से और आसान होगी यूपी में निवेश की राह

लखनऊ, 6 अगस्त। उत्तर प्रदेश सरकार निवेशकों की सुविधा और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को नई ऊंचाई देने के उद्देश्य से निवेश मित्र पोर्टल को और आधुनिक बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में निवेश की नोडल संस्था इन्वेस्ट यूपी 'निवेश मित्र 3.0 'पर गंभीरता से काम कर रही है। निवेश मित्र का यह नया संस्करण न सिर्फ प्रक्रिया को सरल बनाएगा, बल्कि मंजूरी के समय, दस्तावेजों की आवश्यकता और विभागीय जटिलताओं में भी भारी कटौती करेगा। योगी सरकार का यह प्रयास उत्तर प्रदेश को देश का सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाने की दिशा में एक बड़ा और ठोस कदम साबित हो सकता है। निवेश मित्र 3.0 से न केवल राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, बल्कि प्रदेश के युवाओं के लिए भी रोजगार के नए द्वार खुलेंगे।

इस योजना के तहत विभिन्न विभागों में दी जाने वाली सेवाओं की समय-सीमा में 30 से 50 प्रतिशत तक की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उदाहरण के लिए, राजस्व विभाग में पहले किसी कार्य के लिए 45 दिन लगते थे, लेकिन अब इसे घटाकर 21 से 30 दिन के भीतर पूरा करने का प्रयास हो रहा है। श्रम विभाग में पहले 30 दिन लगते

थे, अब यह सिर्फ 5 दिनों में निस्तारित किए जाने का प्राविधान किए जाने का प्रयास है। इसी तरह, पर्यावरण मंजूरी (UPPCB) के लिए जहां पहले 120 दिन लगते थे, अब सिर्फ 21 दिन में प्रक्रिया पूरी की जा सके इसके लिए प्रयास जारी है। वहीं, अग्निशमन विभाग की मंजूरी को 15 दिन के बजाय 5 दिन करने और बिजली विभाग में पहले जो कार्य 66 दिन में होते थे, उसे 40 दिन में पूरे करने का प्रयास किया जा रहा है।

निवेश मित्र 3.0 के माध्यम से योगी सरकार का उद्देश्य केवल समय ही नहीं, बल्कि दस्तावेजों की संख्या में भी बड़ी राहत देने का है। राजस्व विभाग में पहले 5 दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती थी, जिसे अब घटाकर सिर्फ 2 करने का प्रयास है। श्रम विभाग में 14 दस्तावेजों की जगह केवल 4 दस्तावेज़ ही पर्याप्त होंगे। पर्यावरण विभाग में पहले 13 दस्तावेज़ों की जरूरत होती थी, अब यह घटकर 6 हो सकती है। अग्निशमन विभाग में 10 की जगह 2 और बिजली विभाग में सिर्फ 4 दस्तावेज़ों से काम चल जाएगा। विभिन्न विभागों में मंजूरी प्रक्रियाओं में लगने वाले दिनों की संख्या में भी उल्लेखनीय सुधार किये जाने के प्राविधान को भी शामिल करने का प्रयास है। जैसे, पर्यावरण विभाग में पहले प्रक्रिया को पूरा होने में 400 दिन तक लग जाते थे, जिसे अब घटाकर 150 दिन किये जाने का विचार हो रहा है।

कीवी- महत्त्वपूर्ण फल

चाइनीज़ गूजबैरी जो कि 'कीवी फल' के नाम से प्रसिद्ध है, एक महत्त्वपूर्ण फल है। कीवी का उत्पति स्थल चीन है, हालांकि कीवी को चीन के अलावा न्यूजीलैंड, इटली, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, पाकिस्तान, ईरान,नेपाल, चिली, स्पेन और भारत में भी उगाया जा रहा है.

भारत में कीवी फल की खेती हिमालय के मध्यवर्ती, निचले पर्वतीय क्षेत्रों, घाटियों तथा मैदानी क्षत्रों में जहां सिंचाई की सुविधा हो, सफलतापुर्वक की जा सकती है। इसकी खेती हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय , सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में की जा रहा है. इसकी खेती मैदानी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल में भी की जाने लगी है.

कीवी में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है. यह अनिंद्रा रोग को दूर करता है और पाचन क्रिया को सही करता है. आयरन का भी बेहतरीन स्त्रोत है. कीवी फल की बेल अंगूर की तरह होती है, सर्दियों में इसके पत्ते झड़ जाते हैं। भारत के हल्के उपोष्ण और हल्के शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र जिनकी समुद्रतल से ऊंचाई 1000 से 2500 मीटर, 150 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा तथा सर्दियों में । डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग 100 से 200 घण्टों का मिल सकता हो, वहां इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। बसन्त ऋतु के दूसरे सप्ताह में बेल में अंकुर फूटने के समय कोहरा नहीं पड़ना चाहिए, और इसके अलावा तेज गर्मी, आंधी तथा ओलावृष्टि से भी पौधों की पत्तियों, फूलों तथा फलों को क्षति पहुच सकती है। इसलिए साथ में वायु अवरोधक तथा उचित सिंचाई का प्रबन्ध करके आसानी से उगाया जा सकता है। इस लेख के द्वारा कीवी फल की खेती कैसे करें, इसके लिए उपयुक्त जलवायु, भूमि, किस्में, देखभाल, पैदावार आदि की जानकारी के बारें में किसान और बागवान भाइयों को अवगत करवाएँगे, जिससे वे कीवी फल की खेती से उत्तम पैदावार प्राप्त कर सकें।

कीवी का पौधा एक बेल होती है जो 9 मीटर तक बढ़ सकती है और यह 4 से 5 वर्ष के बाद फल देना शुरू कर देती है. अंगूर की बेलों की तरह ही इसकी बेलें बढ़ती हैं।

फूल आने से फसल पकने तक की अवधि लगभग 100 दिन होती है. कीवी को पाले से बचाना बहुत जरुरी होता है. इसके फल नवम्बर महीने से पकने शुरू हो जाते हैं. कीवी को काफी पानी की आवश्यकता होती है इसलिए सिंचाई का उचित प्रबंध होना चाहिए.

कीवी फल की खेती के लिए गहरी, उपजाऊ, अच्छी जल निकासी वाली, बलुई रेतीली दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। जिसका पीएच मान 5.0 से 6.0 के बीच हो और पानी का समुचित निकास हो सके वह कीवी फल की बेलों की बढ़ोत्तरी के लिए सबसे उपयुक्त होती है। इसकी बेलें ज्यादा लवणयुक्त भूमि के प्रति सहनशील हैं और साधारणतया इसको 0.25 पीपीएम से कम बोरान व सोडियम लवण तथा 0. ।5 से कम विद्युत चालकता, जिसका पीएच ।.3 से कम हो ऐसी भूमि में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है।

किस्में

भारत में कीवी फल की खेती की प्रमुख मादा किस्में एलिसन, ब्रूनो, हेवर्ड, मोन्टी और एबट तथा नर किस्में एलीसन व तोमुरी हैं। जो कि एक्टीनिडिया डेलीसियोसा के अन्तर्गत आती हैं। चीन में लगभग दो तिहाई उत्पादन एक्टीनिडिया चाइनेन्सिस का होता है। इस कीवी फल किस्म के फल कम रोंयेदार और पकने पर चिकने हो जाते हैं। भारत में उपलब्ध किस्मों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है, जैसे-

एबट- इस कीवी फल किस्म का मध्यम परिमाण वाला अण्डाकार फल, स्वाद में मीठा, फूल का अन्य किस्मों से अपेक्षाकृत पहले खिलना, फल का औसतन भार 50 से 60 ग्राम, अपेक्षाकृत कम शीतन घंटों की आवश्यकता होती है।

एलिसन- इसका फल लम्बाई के अनुपात में कुछ मोटा, मीठा, एबट के बाद फूलने और मध्य समय में पकने और अधिक पैदावार देने वाली किस्म, एबट से मिलता जुलता फल, फल का भार लगभग 60 से ।0 ग्राम होता है।

ब्रूनो- इसका फल बड़े आकार का लम्बूतरा, गहरे भूरे रंग का, अधिक पैदावार देने वाली किस्म, हेवर्ड की अपेक्षा फल छोटा, फल का भार लगभग 60 ग्राम होता है।

हेवर्ड- इस कीवी फल किस्म के फल अन्य किस्मों से अपेक्षाकृत गोल, आकार में बड़ा, देरी से फूलने वाली किस्म, लम्बी अवधि तक 4 से 6 महीने भण्डारण योग्य फल, अधिक प्रचलित किस्म, फल कुछ कम मिठास वाला, फल का औसतन भार लगभग 90 से 120 ग्राम होता है।

मौन्टी- कीवी फल किस्मों में सबसे बाद फूलने वाली, अधिक फलदायक और ज्यादा फलन वाली किस्म, फल लम्बूतरा, परन्तु डण्डी की ओर कुछ नुकीला, फल का औसतन भार 60 से ।0 ग्राम, फल विरलन आवश्यक है।

किवी फल की खेती के पौधे बीजू पौधे पर बडिंग या कलम करके तैयार किए जाते हैं, विधि इस प्रकार है, जैसे-

बडिंग- कीवी फल के बीज से पौधे तैयार करने के लिए बीज पूर्ण रूप से पके फलों से लें। बीजों को फलों से निकाल कर अच्छी तरह साफ करके छाया में सुखायें। अच्छे अंकुरण के लिए बीजों को एक सप्ताह के अन्दर ही बीज देना चाहिए। मध्यवर्ती ठण्डे पहाड़ी क्षेत्रों में बीज को सीधा क्यारियों में लगाकर मल्चिंग करें।

किन्तु मध्यवर्ती गर्म क्षेत्रों में बीजों को लगभग 10 सप्ताह दिसम्बर से फरवरी या जनवरी से मध्य मार्च तक गीली रेत में रख कर स्तरीकरण (स्टैटिफिकेशन) करके फिर नर्सरी में लगायें। इसके बाद क्यारियों पर मल्चिंग करें। जुलाई तक पौध पर छाया रखें, यदि फलों से बीज निकलने के बाद उन्हें 1 हफ्ते में बीज दिया जाए तो अंकुरण अच्छा होता है। जब इनमें 4 से 5 पत्ते आ जाये तो मई या जून महीने में नर्सरी में लगायें। एक वर्ष पुराने पौधों पर टंग ग्राफ्टिंग जनवरी से मध्य फरवरी तक करें।

कलम लगाकर- सामान्यतया कलम लगाने के लिए शीशे या पोलीथीन के बने घर जिसमें फुहार की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। लकड़ी के बने बक्सों, जिसमें बालू, सड़ी खाद, मिट्टी, लकड़ी का बुरादा और कोयले का चूरा 2-2-1-1 के अनुपात के मिश्रण बनाकर भर लेते हैं।

कीवी फल की दिसम्बर से जनवरी के महीने के कटाई-छंटाई के दौरान निकली शाखाओं को जमीन में दबा देते हैं और फरवरी से मार्च के महीने में ज्यों ही थोड़ा सा तापमान बढ़ जाता है, उस समय शाखाओं को जमीन से निकालकर 15 से 20 सेंटीमीटर की कलमें, जिसमें कम से कम तीन कलियाँ हों, के निचले शिरों को 2500 मिलीग्राम प्रतिलिटर पानी इन्डोल ब्यूटारिक एसिड और 2500 मिलीग्राम प्रतिलिटर पानी नैपथलिन एसिटिक एसिड के मिश्रित घोल में 25 से 30 सैकिंड डुबोकर लकड़ी के बक्सों में लगा देते है।

पाली हाउस में रखे इन वक्सों को 15 से 20 मिनट के अन्तराल पर क्रमश: 2 से 3 मिनट तक फुहार को कम से कम 5 से 6 घंटे दिन में उपलब्ध कराते रहें। इस विधि से लगाने में कम से कम 85 से 90 प्रतिशत सफलता होती है। अगले वर्ष दिसम्बर से जनवरी के महीने में इन कलमों को फुहार घर से निकालकर पौध रोपण के लिए लगाया जा सकता है।

बागवानी से कमाएं लाखों

सघन खेती के सहारे बागवानी से 5 लाख रूपए कमा रहा किसान

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के गांव मरोठी के निवासी हेमराज गुप्ता ने अपनी मेहनत के जरिए मिट्टी से सोने को निकालने का कार्य किया है. खुशी की बात तो यह है कि इस प्रगतिशील बागवान ने सेब पैदावार के पुराने तरीके के छोडकर खेती के आधुनिक तकनीक को अपना करके 5 बीघा जमीन से 5 लाख रूपए को कमाया है. आज सेब की खेती के लिए नई तकनीक को अपनाकर ये बागवान इलाके में दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है. निवासी हेमराज गुप्ता कहते है कि उन्होंने सघन खेती में पुरानी फसल के एक पेड़ की जगह रूट स्टॉक के 15 से 20 पौधों को लगाने का कार्य किया है. इससे अब दुगनी पैदावार होने के साथ ही उनकी आमदनी भी दुगनी होती जा रही है. यही नहीं सघन खेती के सहारे वह सेब के पौधों के बीच अन्य मौसमी सब्जियां व दालें उगाकर भी मुनाफा ले रहे है. पास के गांव के दो लोगों को भी खेती में मदद के लिए स्थाई रोजगार को दे रखा है. वह सेब के सीजन के दौरान 10-12 लोगों को रोजगार दे देते है.

दो से तीन सालों में लगते सेब

उन सभी का कहना है कि सेब की परंपरागत खेती की अपेक्षा क्लोनट रूट स्टॉक पर तैयार बगीचों में कुल दो से तीन सालों में फल लगना शुरू हो जाते है. जबकि सेब की पुराने तरीके की खेती के बगीचों में फल आने में 10 साल से ज्यादा लग जाते है.

इस तरह से करें खेती

खेती में नई तकनीक को अपनाने वाले हेमराज गुप्ता कहते है कि पुराने तरीके से सेब की खेती पर उनके पांच बीघा बगीचे में 60 से 70 बॉक्स सेब को निकालते थे. इस दौरान उनको अपनी मेहनत का पूरा पैसा भी नहीं मिलता था. ऐसे में उन्होंने सघन खेती के मॉडल को अपनाया और बगीचे में सुधार किया है. इसके लिए बागवानी विभाग ने पांच बीघा जमीन के लिए उन्नत नस्ल के 1 हजार के सेब के पौधों को उपलब्ध करवाएं. उनके बगीचे पहली बार सेब के 200 बॉक्स निकले है. इस बार उनको सेब की खेती से पांच लाख तक की कमाई हुई है.

कश्मीर एलपीजी वितरक संघ ने सतीश शर्मा से मुलाकात की

श्रीनगर 06 अगस्त। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी और युवा सेवा एवं खेल मंत्री, सतीश शर्मा ने जग मोहन सिंह रैना के नेतृत्व में कश्मीर एलपीजी वितरक संघ के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की।

प्रतिनिधिमंडल ने बार-बार गैस की कमी के कारण वितरकों और उपभोक्ताओं को होने वाली कठिनाइयों पर प्रकाश डाला।

प्रतिनिधिमंडल ने एलपीजी आपूर्ति में बार-बार होने वाली रुकावटों का मुद्दा उठाया और कहा कि इसके लिए जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के बार-बार बंद होने और चल रहे रखरखाव कार्यों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से कश्मीर घाटी और दूरदराज के इलाकों में गैस सिलेंडरों का समय पर परिवहन बाधित हो रहा है।

प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से एलपीजी वितरकों को वर्तमान विनियमित सीमा से अधिक अतिरिक्त गैस सिलेंडर रखने की विशेष अनुमति देने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस तरह के प्रावधान से सड़क जाम या प्रतिकूल मौसम के दौरान, विशेष रूप से पहाड़ी और ऊँचाई वाले क्षेत्रों में, गैस की कमी को रोकने में मदद मिलेगी।

सतीश शर्मा ने प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करते हुए उनकी चिंताओं की वास्तविक प्रकृति को स्वीकार किया। उन्होंने एसोसिएशन को आश्वासन दिया कि इस मामले को तेल विपणन कंपनियों और आपदा प्रबंधन विभागों सहित संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा।

मंत्री ने कहा, सरकार हर घर तक आवश्यक वस्तुओं, विशेष रूप से रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम उचित सुरक्षा मानदंडों के तहत भंडारण सीमा में अस्थायी छूट सहित सभी संभव समाधानों का पता लगाएंगे।

उन्होंने एफ़्सीएसएंडसीए विभाग को जिला प्रशासन और तेल कंपनियों के साथ एक संयुक्त समीक्षा करने का निर्देश दिया ताकि आपूर्ति बाधित होने की क्षेत्रवार संवेदनशीलता का आकलन किया जा सके और उपयुक्त भंडारण तंत्र की पहचान की जा सके।

मंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सभी संवेदनशील जिलों में अग्रिम शीतकालीन भंडारण योजनाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है और आपूर्ति श्रृंखला दक्षता बनाए रखने के लिए नागरिक प्रशासन, ट्रांसपोर्टरों और तेल कंपनियों के बीच समन्वय के महत्व पर बल दिया।

डीडीसी डोडा ने हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों की समीक्षा की

डोडा 06 अगस्त। जिला विकास आयुक्त डोडा, हरविंदर सिंह ने जिले में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों की समीक्षा हेतु डीसी कार्यालय परिसर, डोडा के मिनी मीटिंग हॉल में एक बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में एडीडीसी डोडा रोशन लाल, एडीसी डोडा अनिल कुमार

ठाकुर, सीपीओ डोडा मनेश कुमार, एसीपी डोडा मुशर्रफअली हाफ़ उप निदेशक रोजगार रफ़ीक अहमद जराल, सीईओ डोडा मोहम्मद हनीफ़ डीआईओ डोडा तारिक काजी, परियोजना अधिकारी डीयूडीए, ईओ एमसी डोडा, सांस्कृतिक अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक एनआरएलएम और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। कई अधिकारी भी बैठक में वर्चुअल रूप से शामिल हुए यह बताया गया कि 9 अगस्त से 11 अगस्त 2025 तक डोडा के सभी ब्लॉकों में तिरंगा रैलियाँ आयोजित की जाएँगी, जिससे जनता में देशभक्ति और एकता को बढ़ावा मिलेगा। यह अभियान 12 अगस्त 2025 को डोडा सामुदायिक भवन में एक विशाल तिरंगा मेले के साथ समाप्त होगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियाँ और जागरूकता गतिविधियाँ शामिल होंगी। डीडीसी ने सभी विभागों को सावधानीपूर्वक योजना बनाने और अधिकतम जनभागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों, पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नागरिकों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों, जागरूकता अभियानों और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार पर ज़ोर दिया। पूरे जिले में अभियान को पूरे उत्साह के साथ मनाने के लिए घनिष्ठ अंतर-विभागीय समन्वय और व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने पर भी ज़ोर दिया गया।

उधमपुर में जिला स्तरीय एनसीओआरडी समिति की बैठक आयोजित

उधमपुर 06 अगस्त। उधमपुर की उपायुक्त सलोनी राय ने नशा नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन और उनके जमीनी स्तर पर प्रभाव का आकलन करने के लिए नार्को समन्वय केंद्र के अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त प्रेम सिंह, पुलिस अधीक्षक संदीप भट्ट, सहायक आयुक्त राजस्व डॉ. उमेश शान और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

अवैध मादक पदार्थों के व्यापार में शामिल व्यक्तियों की पहचान में हुई प्रगति और एनडीपीएस अधिनियम के तहत जाँच की स्थिति पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

उपायुक्त ने मादक पदार्थों के तस्करों की संपत्ति तत्काल ज़ब्त करने, मादक पदार्थों की अवैध खेती पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी उपाय करने, मादक पदार्थों के सेवन के शिकार लोगों के पुनर्वास में सहायता प्रदान करने और कोचिंग सेंटरों सहित सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने नशा मुक्त पंचायत अभियान के समुचित कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया।

विभागों को जन जागरूकता के लिए, विशेष रूप से जमीनी स्तर पर, सूचना एवं संचार तकनीक गतिविधियाँ आयोजित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रमुख केंद्रों की पहचान और निगरानी तथा नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन पर भी ज़ोर दिया गया। औषधि एवं खाद्य नियंत्रक को फार्मेसियों में 100 प्रतिषत सीबीएस बिलिंग सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया। ईटीओ को जिले में जंगली भांग की वृद्धि का सक्रिय रूप से पता लगाने और उसे नष्ट करने के लिए टीमें गठित करने का निर्देश दिया गया।